श्री धर्मेंद्र प्रधान : माननीय सभापति जी, आदरणीय राजीव शुक्ला जी ने प्रश्न पूछा है कि आदिवासी युवाओं के बारे में क्या करना है। अभी मेरे senior colleague, श्री अर्जुन मुंडा जी ने 'पीएम जनमन योजना' के अंदर स्किल डेवलपमेंट के बारे में जो प्रमुख कंपोनेंट है, उसके बारे में उल्लेख किया है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, स्किल डिपार्टमेंट और सभी राज्य सरकारें फोकस्ड तरीके से देश के ग्रामीण युवाओं की स्किल कैपेसिटी बढ़े, इसके संबंध में योजना बना रही हैं। मैंने इसका एक विवरण रखा है।

श्री राजीव शुक्ला : सर, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ के साथ गवर्नमेंट collaboration कर रही है, जैसे Blinkit, Apna, Quess आदि हैं। क्या ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कुछ फायदा हो जाए या इनको सेलेक्ट करने का कोई प्रोसीजर है? ...(**समय की घंटी**)...

श्री धर्मेंद्र प्रधान : सर, हमारी सरकार में पारदर्शिता है, बाकी मेरे मित्र राजीव शुक्ला जी की दृष्टि में चाहे जो दिखे, हमारे यहां तो सारे पारदर्शी हैं।

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 2 p.m. today.

[Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part – I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise]

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock,
MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS 2023-2024

MR. CHAIRMAN: Supplementary Demands for Grants 2023-2024; Shri Pankaj Chaudhary.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : महोदय, मैं अनुपूरक अनुदान मांगों, 2023-24 को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

SHORT DURATION DISCUSSION

*Economic Situation in the Country

श्री जयराम रमेश (कर्नाटक) : सर, हाउस में कोई भी कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं हैं।। have a point of order. ...*(Interruptions)*...

---

* Further discussion continued from the 5th December, 2023.

MR. CHAIRMAN: Now, we will take up the Short Duration Discussion. ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेश : सर, हाउस में कोई भी कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

MR. CHAIRMAN: Further discussion on the "Economic Situation in the country", raised by Shri Derek O'Brien on 5th December, 2023. On 5th December, 2023, Shri Rakesh Sinha had concluded his address while participating in the discussion. Any other Member desiring to speak, that was indicated. ...*(Interruptions)*...

श्री जयराम रमेश : सर, हाउस में कोई भी कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं हैं।

MR. CHAIRMAN: The telepathy of Shri Jairam Ramesh is so strong over-taking physical hurdles. The hon. Minister, who is deeply committed to parliamentary practices and has been in this House as much as you have been or perhaps more, is very much here. ...*(Interruptions)*... Hon. Members, I had indicated that we would like to accommodate as many Members as possible. Some names have come. We would try to accommodate the hon. Members. Now, Shri K.R.N. Rajeshkumar. ...*(Interruptions)*... Now, Prof. Ram Gopal Yadav.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) **:** धन्यवाद सभापति जी।

MR. CHAIRMAN: We will have benefit of his thoughts on a very important subject, very wholesomely initiated by Shri Derek O'Brien, impactfully initiated. ...*(Interruptions)*...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, what is going on! You are becoming very complimentary to Shri Derek O' Brien. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Let me tell you, our equation always has been the same. But, right now, what has happened is, you seem to have acquired a new intellectual ability to find it out.

प्रो. राम गोपाल यादव : सर, आप 20-22 सेकंड के समय को एडजस्ट करवा दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Sir, I am here to take care of everything.

PROF. RAM GOPAL YADAV: Okay, Sir.

MR. CHAIRMAN: I will drive the technology rather than be driven by it.

प्रो. राम गोपाल यादवः श्रीमन्, आपने मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कल से भारत की आर्थिक स्थिति पर हो रही चर्चा को सुन रहा हूं और बहुत सारे आंकड़े भी दिए गए हैं। ये आंकड़े आम तौर पर भूलभुलैया होते हैं, इन्हें पता नहीं कौन बनाता है, कैसे बनाता है। किसी को इधर के लोग कंट्राडिक्ट करते हैं, तो...

श्री सभापति : और कहां बनाता है, इस ग्लोब के किस हिस्से में बनाता है?

प्रो. राम गोपाल यादव : सर, मैं वैसे भी ज्यादा नहीं बोलता हूं, इस बात को आप भी जानते हैं। आप इसको अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा, कल जब इधर से लोग बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं, जिनको यहां के धरातल की कोई जानकारी नहीं है। जिनको यहाँ के धरातल की कोई जानकारी नहीं है। सच बात तो यह है कि मोदी जी के परिश्रम और मोदी जी के नाम से ये लोग आ जाते हैं, लेकिन गाँव में देखना नहीं चाहते हैं कि क्या हो रहा है, कितना दिया जा रहा है और कुछ लग रहा है या नहीं। जैसे मोदी जी से प्रचार करा दिया -'हर घर जल, हर घर नल'।

श्री सभापति : नहीं, 'हर घर नल, तो फिर जल'।

प्रो. राम गोपाल यादव : 'हर घर नल-हर घर जल'। Sorry. Thank you, Sir. जब हम अपने इलाके में जाते हैं, तो लोग हमसे मिलने आते हैं। क्योंकि उनकी समस्याएं होती हैं, इसलिए कोई मदद के लिए आता है, कोई किसी काम के लिए आता है। मैं अक़सर उनसे पूछता हूं कि बताइए, क्या आपके गाँव में हर घर में पानी पहुंच गया है? मैं कई गाँवों में ब्याह-शादियों में जाता हूं। सारी पक्की गलियाँ, जो विधायकों ने, सांसदों ने, या ब्लॉक जिला पंचायतों ने बनवा दी थीं, वे खुदी पड़ी हैं, क्योंकि वहाँ से पाइपलाइन्स जानी हैं। वहाँ पाइपलाइन नहीं बनी, टंकी नहीं बनी। यह क्यों नहीं बनी? लोग जो बताते हैं, उसके अनुसार गुजरात वाले लोग - आप उसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, वहाँ के लोग कहते हैं कि सारे ठेकेदार गुजरात के थे और पैसा लेकर चले गए। (...**व्यवधान**...) लोग ऐसा कह रहे हैं। आप सुनिए, आप रिकॉर्ड में देख लीजिए कि ऐसा है कि नहीं। मैं यह ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन कोई गाँव ऐसा नहीं है, जिसमें हंड्रेड परसेंट घरों में पानी गया है, किसी गाँव में तो एक भी घर में पानी नहीं गया है। आपको इसको देखने की जरूरत है, इन लोगों से कहने की जरूरत है कि इसको कीजिए। आप या तो प्रधान मंत्री जी से, इतने बड़े आदमी से प्रचार मत कराइए या फिर उस काम को पूरा कराइए। चिदम्बरम जी ने कल कहा था कि जमीन पर नहीं दिखता है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी है, दुनिया में ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। सुशील मोदी जी ने कहा कि अगर नीचे नहीं दिखता

तो तीन राज्यों में जनता ने कैसे जिता दिया? लेकिन अगर मैं यह पूछूँ कि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्णाटक में आप क्यों हारे, तो क्या जवाब है? यह कोई तर्क नहीं है, यह कोई पैरामीटर नहीं हो सकता है। अगर आंकड़े की बात करें, तो यह सही बात है कि पाँचवीं अर्थव्यवस्था है, सारा मामला बहुत बल्क है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी में देखेंगे, तो पाएंगे कि हम 194 देशों में से 133वें नंबर पर हैं। जो आम आदमी की स्थिति है, वह यह दर्शाती है कि हम दुनिया में कहाँ स्टैंड करते हैं, भले ही पाँचवें नंबर पर क्यों न हों! हम 194 देशों में से 133वें नंबर पर हैं।

सर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पर क्या कहता है? यह रिपोर्ट बताती है कि 125 देशों में से हमारी स्थिति 111 वें नंबर पर है। हालांकि एफएसएसआई ने इसका कंट्राडिक्शन किया है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आंकड़े कौन बनाता है, कैसे बनाते है। इसके आंकड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत है, तो मैं यह आंकड़ा भी दे रहा हूं कि हम कहाँ stand करते हैं, इसलिए केवल आंकड़ों पर भरोसा मत कीजिए।

महोदय, राकेश सिन्हा साहब अभी यहाँ पर नहीं हैं। उन्होंने कई उदाहरण दिए थे। मैं जब अपने क्षेत्र में रहता हूं, तो मुझसे सैकड़ों लोग मिलते हैं। मेरे पास ऐसे तमाम लोग आते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, कुछ मदद करवा दीजिए। अभी परसों ही एक ऐसी स्थिति हुई, जब मैं वहाँ था। - मैं यहाँ पर दो-तीन दिन नहीं था, मैं वहाँ था, तब ऐसी ही स्थिति हुई। एक आदमी बैठा था, मैंने उससे पूछा कि बताओ, तुम्हारा क्या काम है? उसने कहा कि सर, मैं अकेले में बात करना चाहता हूं। मैंने बाकी लोगों से कहा कि अगर सबकी बात हो गई हो, तो चले जाएं, नहीं तो मैं इनको लेकर जाऊं। मैंने कहा कि आप चाय पीकर जाएं। उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, उसकी सहेलियाँ, जिनकी शादी हुई है, वे थोड़े संपन्न परिवार की हैं। उसने मुझसे नहीं कहा, अपनी माँ से कहा कि जैसे हमारी और सहेलियों की शादी के लिए लहंगा बनाया जाता है, वैसी हमारी हैसियत नहीं है - क्योंकि लहंगा तो टीवी के ज़रिये अब ऐसा दिखने लगा है कि यह 1 करोड़ रुपये का बनता है, लड़कियाँ 50 हज़ार का लहंगा भी पहनती हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन सभी लड़कियों का मन तो होता ही है। गरीब लड़की हो या कोई और भी हो, वह शादी के दिन बेहतर लहंगा पहनना चाहती है, 1 करोड़ रुपये का नहीं, तो 10-15 हज़ार रुपये का ही लहंगा बनवा दो - मेरी पत्नी से उनकी बेटी ने कहा था। मैंने कहा कि हम इसकी व्यवस्था करवा देंगे, आप निराश मत होइए। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है, जैसा आप कहते हैं कि उन्होंने यह कह दिया। उज्ज्वला योजना में गैस का सिलिंडर देते हैं। उसमें यह तो पता कीजिए कि जो सिलिंडर दिये गये, उनमें से कितने भरे गये। लोगों के पास उनको भरवाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। 80 फीसदी लोगों के पास उनको भरवाने के लिए पैसा नहीं है। पड़ोसियों ने उनसे यह कह कर ले लिया कि आप सिलिंडर हमें दे दीजिए। उसमें यह स्थिति है।

सर, मैं तो अब यह चाहता हूँ कि लोग गाँव में जाकर देखें कि वहाँ जो शौचालय बने हुए हैं, उनका उचित प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। वहाँ कहीं पर बकरियाँ बँधी हैं, कहीं पर लोगों ने उसमें भूसा भर दिया है। वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। यह स्थिति है। इस ग्राउंड रियलिटी को नहीं दर्शाया गया है। यहाँ तो कम से कम ऐसी बात कहिए, जिसको सुनने वाला यह समझे कि हाँ, यह सही बात कही जा रही है। इसमें सुनने वाला क्या कहेगा, यह तो उसके सिर के ऊपर से निकल जाएगा।

प्रधान मंत्री जी ने स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी योजनाएँ बनायीं। यह सही है कि 5 लाख रुपये तक की चिकित्सा की व्यवस्था की गयी, लेकिन उसको डॉक्टर नहीं मान रहे हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि इलाहाबाद की एक एमपी हैं, जो कि बहुगुणा जी की बेटी, रीता जी हैं, उन्होंने एक मरीज को गंगाराम अस्पताल में भेजा, तो उसने वापस कर दिया कि हम इस कार्ड को नहीं मानते। उन्होंने चिट्ठी लिखी और मुझसे व्यक्तिगत रूप से आकर कहा कि आप हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं, इसमें कुछ मदद कीजिए, क्योंकि उसने लाखों रुपये का बिल बना दिया और वह इसको मान ही नहीं रहा है। मैंने गंगाराम अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट से बात की। मैं उनको जानता हूँ। वे एम्स की गवर्निंग बॉडी में मेरे साथ थे, उनसे कभी-कभी मुलाकात हो जाती थी। उन्होंने कहा कि इस कार्ड का कोई ठिकाना नहीं है। अब आप यह देखिए कि यह गवर्नमेंट का ऑथेंटिक कार्ड है, लेकिन इसलिए कि उस पर आप जब ज्यादा पेमेंट लेंगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि 10 रुपये की जो चीज़ है, उसका दाम 1,000 रुपये ले रहे हैं, इसलिए कोई इसका फायदा नहीं दे रहा है। कुछ निजी अस्पताल ऐसे हैं कि 500 रुपये की दवा दी और वे 5,000 रुपये का बिल बना देते हैं कि हमें पैसा मिल जाएगा। यानी इसमें लूट हो जाती है। हमारे यहाँ जो out of pocket expenditure है, वह दुनिया में सर्वाधिक है। हमारे ही हेल्थ विभाग की और दुनिया के दूसरे देशों की यह रिपोर्ट है कि out of pocket expenditure के कारण 2-3 परसेंट लोग poverty line के नीचे चले जाते हैं। ...(**समय की घंटी**)... अगर एक घर में कोई व्यक्ति कैंसर का मरीज हो गया, तब उसकी तो जमीन बिक गई। फिर out of pocket expenditure कैसे कम हो? मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि यह सबसे बड़ी बात है। अगर इसको कम कर देंगे, तो ठीक रहेगा। आपकी गवर्नमेंट ने कोशिश की है, no doubt, लेकिन उसका implementation सही तरीके से नहीं हो रहा है। कुछ दूसरे देशों में, जैसे इंग्लैंड वगैरह में यह केवल 2-3 परसेंट है। यह पश्चिमी देशों में बहुत कम है। यहाँ अगर इसकी व्यवस्था नहीं होती है, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, आप कहते रहिएगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन आंकड़ों पर मत जाइए। गाँव में, देहात में, ग्रामीण इलाकों में जाकर असलियत को देखें, लोगों से बात करें और कमियों को दूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Hon. Chairman, Sir, I am very thankful to you for giving me this opportunity. As on 31st March, 2023, the debt of the Central Government was Rs.155.6 lakh crore. This is 57.1 percent of GDP in financial year, 2022-23. When compared with unemployment rate as on July, 2023, it is 7.95 percent. During the first quarter of the current financial year, the manufacturing sector was not performing well to the expected level. But, it seems the second quarter of this part of growth in the manufacturing sector is there. Under these situations, a big question which arises in everybody's mind is whether the Government will be able to become a five trillion economy by 2025. That has to be looked into. In the employment sector, there is a big gap. The Government had set the ambitious task of providing one million jobs by the end of 2023. We are in the month of December, only a few days are left at the end of 20 years. It has to be

considered by the hon. Minister. Sir, we have given to ourselves a cooperative federalism. The Centre has the responsibility to take care of the financial condition of the States. There are certain parameters which every State has to follow. But, what is happening in the State of Andhra Pradesh is known to everybody. As on date, the debt of the State is Rs. 11,28,992 crores. As per the information given in an answer a Parliamentary question, the debt of the State Governments at the end of the financial year 2022-23 is estimated to be about 28 per cent of GDP.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.)*

The debt percentage of the State Government of Andhra Pradesh falls within 28 per cent of GDP. As per the statement of RBI, ...*(Interruptions)*... Sir, what is happening every day? ...*(Interruptions)*... State is a part of the country. Every day they are interrupting.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have to speak on the Indian economic situation. ...*(Interruptions)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: It is about finance and Andhra Pradesh is a part of India. ...*(Interruptions)*... It is a part of India, not outside. Sir, it is as per the record of the RBI. ...*(Interruptions)*... As per the statement of RBI, the State Government of Andhra Pradesh raised Rs. 46,443 crores from market. It repaid only Rs.10,339 crores. It has not even paid half of the amount borrowed from market. In reply to my parliamentary question, on 1st August 2023, it has been inter alia stated that guarantees of Rs. 22,363 crores during financial year 2021-22 and Rs. 57,444 crores during financial year 2022-23 have been issued by the State Government of Andhra Pradesh.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The subject is 'Position of Indian Economy', your speech will be examined, please. You have to speak on Indian economy.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: The State Government has pressed into service its State Public Sector companies, Special Purpose Vehicles and other equivalent instruments into borrowings and thereby attempted to deceit the Government that its net borrowings are within the prescribed limit. But, the Central Government has stated that the borrowings by the State Public Sector companies

and other equivalent instruments ...*(Time Bell rings.)*... where principal and the interest are to be serviced out of the State Budgets.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over....*(Time Bell rings.)*...

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: In spite of this advisory issued by the Central Government, they did not stop the borrowings.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Kanakamedala Ravindra Kumar, please conclude; your time is over. The time was three minutes, please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Hon. Chairman has given ten minutes' time to my colleague Member. The State is becoming a debt-ridden State, the debts of the Government are increasing day by day.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am inviting other person now. Your time is already over; please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: As per records, the CAG itself has observed the Government is making heinous mistakes in financial management. The CAG itself said about the financial year ending on 22nd March that it has borrowed Rs. 1,20,000 crores without showing or telling the Assembly.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: The Audit certificate in the name of qualified opinion was given in the history of the country. ...*(Time Bell rings)*... She said that she can tell the debts of the corporation as per what is given to her, but she is not giving full information about the debts of the corporation. CAG says that for every rupee spent in 2021-22, there is a debt of 51 paise. *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am inviting other speaker now; it will not go on record any more.

The next speaker is Shri Jethmalani. ...*(Interruptions)*... Please speak on the subject. ...*(Interruptions)*... Your time is fifteen minutes. ...*(Interruptions)*...

---

* Not recorded.

Nothing is going on record. Please follow the rules. ...*(Interruptions)*... Now, Shri Mahesh Jethmalani.

SHRI MAHESH JETHMALANI (Nominated): Hon. Deputy Chairman, I thank you for this opportunity to speak on this most important subject on the economic health of this country. Sir, the essence of the criticism from the Opposition Benches led in the main by the former Finance Minister, Mr. Chidambaram and hon. Member, Mr. Derek O' Brien is that there is no point in the present Government tom-tomming about India's high growth rate. On the ground, this high growth rate has not translated into indicators vital for the poor such as high employment and low inflation. Sir, Mr. Chidambaram, as usual, has shifted the goalpost, but this shift is heartening in one respect. In April this year, citing the World Bank's latest GDP estimate for India, he attacked the Government and he said that it was only Mr. Modi, who was boasting about the economic growth rate in the country. The World Bank Development Update, which he relied on, had cut India's growth forecast to 6.3 per cent from the earlier 6.6 per cent. Mr. Chidambaram, however, has been repeatedly wrong about his economic forecast regarding the NDA Government's policies and programmes. Again, the World Bank's estimates have proved to be hopelessly wrong and in the last two quarters, India's growth rate has been very impressive and way above, the world average growth rate at 7.6 per cent and 7.8 per cent. Now, Sir, Mr. Chidambaram, in a clear case of what can only be called convenient amnesia, accepts the growth rate. He doesn't dispute these figures though he earlier did and criticized us for boasting about it and predicting this high growth rate. Now he has moved on from his blind reliance on foreign forecast about India's growth, but he laments now that what use of high growth rates if high unemployment and high inflation persists. As for employment, Mr. Chidambaram relies upon the Periodic Labour Force Survey. Sir, it is a very good survey. It has got good methodology and its data is unexceptionable. So, let us go by the PFLS data. First, the data reflects -- I am afraid I will have to read this out because there are figures involved; normally, I don't like reading it out; normally I would like to address ad hoc, extempore, but I will read it out -- that both in quantity and quality, the employment situation improved consistently before the Covid pandemic. From 2017-18 to 2019-20, regular wage/salaried employees increased by 1.5 crores, a growth of 13.2 per cent; the increase among females was 0.72 crores or 29.4 per cent; and that for males 0.79 crores or 8.8 per cent. Further formal employment increased by 1.2 crores or 25.3 per cent. The quantity of employment improved pre-pandemic as well. From 2017-18 to 2019-20, the UR, that is, the unemployment rate, which captures long-term unemployment decreased from

6 per cent to 4.8 per cent. The Labour Force Participation Rate, LFPR, increased from 49.8 per cent to 53.5 per cent; the Workers' Population Ratio increased from 46.8 per cent to 50.9 per cent. These changes were widely dispersed in rural and urban areas and for males and females. Now, Sir, this is the pre-Covid. As everybody knows, there was a setback to the economy during Covid. But let us come to the post-Covid situation. Post-Covid urban employment registered a robust V shape recovery after the adverse impacts during lockdown and the second wave of the pandemic. Compared to the October-December 2019 quarter, in the April-June 2023 quarter, the worker population ratio increased from 44.1 per cent to 45.5 per cent. The labour force participation ratio has increased from 47.8 per cent to 48.8 per cent. Unemployment rate has declined from 7.8 per cent to 6.6 per cent. Sir, as urban areas were most affected by the Pandemic, the complete recovery in employment in urban areas is crucial. The unemployment rate recorded in April-June 2023 quarter is the lowest. This is important. The unemployment rate recorded in April-June, 2023 quarter is the lowest over the last five years.

The annual PLFS survey data on which Mr. Chidambaram relies upon, which covers both rural and urban areas, also shows complete recovery in employment post-Pandemic. This pattern of complete recovery in employment is reflected similarly if you look at data from the EPFO and the MGNREGA. The monthly EPFO data discloses — this is again very important statistic — net additions in August, 2023, has been 116 per cent higher than in December, 2019. Hon. Chairman, you know that EPFO data the additions to which is employees' contribution, there is 116 per cent addition to the EPFO which reflects the quantum of employees that have risen and the quantum of employment, therefore, risen. The demand for work — this is also very important — under NREGA in December, 2022, is half the demand when compared to 2023. Sir, NREGA is chosen when people are desperate for work where there is no other work. It is now half the demand. It shows that the demand for distress work has declined sharply in rural areas.

Finally, as per PLFS — again the same survey which Mr. Chidambaram relies upon — the unemployment rate for person, this is an overall picture, aged 15 and above, at the all India level, has decreased to 3.2 per cent only in 2022-23 from 4.1 per cent in 2021-22. This is the state of unemployment which Mr. Chidambaram harps on.

As regards inflation, as per data released by the National Statistics Office, the CPI was 4.25 per cent in May this year, 4.81 per cent in June this year and 5.02 per cent in September, well below the RBI's upward tolerance limit of 6 per cent. We have been below 6 per cent continuously. Ultimate test — forget figures and

statistics — is this. Employment and inflation are matters of great concern to poor. Ultimately, the only test whether unemployment and inflation is hurting people is the election results. Sir, the overwhelming results recently show that people are satisfied with employment and inflation levels.

Sir, a former British Prime Minister is alleged to have said that there are three kinds of lies — lies, dam lies and statistics. Mr. Chidambaram is an excellent juggler of facts. I leave it to hon. Members of the House and others watching this debate to decide which category do Mr. Chidambaram's statements fall within. Sir, perhaps, it merits emphasis that, as Finance Minister, Mr. Chidambaram, presided over some of the greatest scams this country has ever seen which devastated our banking sector, ruined investors and severely retarded economic growth and the very important indicators of employment and inflation, which he has so eloquently waxed about in this House. Sir, the only silver lining I may add personally is that his activities and those of his Government have, in their aftermath, enriched a battalion of lawyers whose earnings I cannot grudge. Sir, hon. Member, Mr. O'Brien, being a leader from a regional party, the TMC, has struck a parochial note. He talks about 8.4 per cent growth rate in West Bengal, which is true. I can't deny that. But, being a Member of a national party, I have all India concerns. But, I do admit to having a soft corner for West Bengal, having studied in a boarding school there from the age of ten to sixteen in that picturesque hill station, Darjeeling. The burden of Mr. O'Brien's song is that India's high growth rate has only enriched billionaires and has widened the inequality gap. I acknowledge, as I said, that West Bengal has a high growth rate of 8.4 per cent, which is above the national average. But, perhaps, an examination of the State-wide data should reveal to Mr. O'Brien where the fruits of economic growth in West Bengal have gone. If per capita income is the measure of economic welfare, then, West Bengal's per capita income is well below the national average. And, in fact, apart from a few North-Eastern States, it is one of the lowest in the country. Then, again, on the question of income inequality, which he talks so much about, the gini coefficient which is now a measure used by economists to measure income inequality income distribution. As a measure of inequality, West Bengal has a coefficient of 0.38, which is the third-largest in the country, and more than the national average. So, if you go by income inequality and income distribution, his State performs the third-worst in the country. Perhaps, as a former quiz master, he needs to ask some questions to himself; and, he may discover some home truths.

Sir, in conclusion, it is the right of the Opposition not merely to ask questions, but to ask incisive and searching questions of the Treasury Benches. But, equally, it behoves the Opposition not to buttress their case with selective facts, slanted

questions, and distorted data. The people of this country deserve to know from their elected representatives the unvarnished truth.

Thank you very much, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Binoy Viswam. You have three minutes.

SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, please give me ten minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is nothing in my hands. It is there in the list here.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, my friends, including my previous speaker Mr. Jethmalani, on the BJP side are trying very hard to pose a picture which is most untrue. Where is the 'V' shaped development, which you are talking about? It can't be seen in the country. The fact is that the people are hungry. The youth is unemployed. The young people are knocking at every door for employment. I ask you what happened to your promise of providing two crore jobs every year. Where is it? Do you know that 22.4 crore Indians are hungry in the country? And, you say that everything is fine here! You live on propaganda. The BJP thrives on propaganda. And, you thrive on propaganda in a very nasty way. What happened to your *Beti Bachao Beti Padhao* scheme? Major share of its fund, to the tune of 42.3 per cent, has gone for propaganda alone. This is the right wing way of development! You forget the poor; you forget the people. You just live on propaganda and spend money on propaganda. This is the real truth of the country today. The economy is in shambles. Unemployment is on the increase, hunger is on the increase, and the people have no huts to live in. Your projects are great but they are not bringing the fruits for the people. Sir, we want a decent life. At this age of ours, when the country has completed 77 years of Independence, in this country, the maximum number of people are illiterate even today. Today, at night, the maximum number of people go to sleep with half stomach. Sir, this is the country in which children below the age of five years are dying the maximum in number. This is the countrywhere the pregnant women are anaemic the maximum. These are WHO statements, and you shut your eyes to this fact. You tell the whole world Vishwaguru, Vishwaguru. No; that Vishwaguru's story is not a real story; it is a story of illusions; it is a story of lies and half-truths, and you tell the world that the whole world is looking at you. (*Time-bell rings.*) Sir, the time has come that the people demand a change in the country. Don't think too much about the victory. That victory is a temporary victory. I can tell you when all the forces of this country which stand for secularism and democracy, if they ever stand together

and hold hands together, we are sure that you can be defeated. The struggle has begun. Don't think that the struggle has ended. It is only a temporary situation. The struggle continues and this House states that the people will win, not the propaganda masters. Sir, Pope Francis has told about one fact. What is that point? (*Time-bell rings.*) Sir, one minute.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes.

SHRI BINOY VISWAM: Sir, Pope Francis said, if all the endeavours of the human beings are centred only for profits, then, the whole ecosystem, the whole ethics, religion, will be in shambles. So, people are important, Sir, not the profits. This is the question. We ask the question to you: Who are important - the people or the profits? We say, the people are important and not your profits. (*Time-bell rings*) You plead for Adanis, Ambanis.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BINOY VISWAM: Your Government is a Adani-Ambani Government. Don't give their figures. You present a rosy picture saying that this country is growing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI BINOY VISWAM: No. This country is growing only for the seven per cent of the population. They are growing, not the people. Your figures are their figures and not the peoples' figures. We stand for the people, not for your figures. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Mahua Maji, you have three minutes.

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड) : उपसभापति महोदय, 'Economic situation in the country' विषय पर मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी भी देश के विकास के लिए आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह मेरुदंड की तरह होता है। यदि वह सीधा न हो, तो देश चरमरा जाता है। हम 21वीं सदी में हैं और विश्व गुरु बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं। मगर चिंता का विषय यह है कि देश में बेराजगारी चरम पर है, जिसका असर हर क्षेत्र में पड़ रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के पूरे होने के बाद ही हम कला, संस्कृति, साहित्य आदि के विकास की बात सोच सकते हैं। अब कला, साहित्य, संस्कृति क्यों - क्योंकि कला, संस्कृति, साहित्य और संगीत मनुष्यों को पशुओं से अलग करता है, देश को सम्मानित स्थान देता है और विश्वगुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक भूखा पेट व्यक्ति देश के विकास में क्या साथ देगा और देश

को विश्वगुरु बनाने की ख्वाहिश को कैसे पूरा करेगा? उन्हें सम्मानजनक रोजगार चाहिए और आर्थिक निश्चिंतता चाहिए। क्या हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वायदा वर्तमान केन्द्र सरकार पूरा कर पाई? यदि कर पाती, तो अब तक 2014 से 2023 तक लगभग 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाती, देश में आर्थिक निश्चिंतता आती और ज्यादा से ज्यादा लोग देश को विश्वगुरु बनाने की मुहिम में लग जाते। अग्निवीर - फौज में लगभग तीन साल की नौकरी। पहले जब एक गरीब का बेटा फौज में जाता था, तो पूरा परिवार निश्चिंत हो जाता था, लेकिन अब तीन साल के बाद जब उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, बूढ़े मां-बाप होंगे, तो वह क्या करेगा? वह तो बेरोजगार हो जाएगा। क्या वह आत्महत्या के बारे में सोचेगा या फिर वह केन्द्र सरकार का जो वायदा है कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, उस वायदे के अनुसार सरकार से राशन लेकर अपने परिवार का पेट पालेगा? इससे उसके आत्मसम्मान का क्या होगा? क्या वह आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होगा? केंद्र सरकार कहती है कि जीडीपी बढ़ रहा है, स्टॉक मार्किट ऊपर जा रही है, लेकिन इससे कुछ बड़े उद्योगपतियों सहित कुछ ही प्रतिशत लोगों को मुनाफा हो रहा है, देश की ज्यादातर गरीब जनता को इससे मुनाफा नहीं हो रहा है। सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, सरकार के दावे के अनुरूप यदि लगभग 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, तो इसका साफ मतलब है कि इतने लोग बेरोजगार हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है कि वे अपने परिवार का पेट पाल सकें, अपनी आय से आटा, चावल, अनाज खरीद सकें। 80 करोड़, यानी देश के लगभग तीन-चौथाई लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय है।

महोदय, सरकार द्वारा किए जा रहे खर्च में भी व्यापक असमानता दिखती है और खर्च की priority आश्चर्यचकित करती है। एक तरफ मनरेगा जैसी गरीबों की योजना के पैसे समय पर स्टेट को देने में आनाकानी हो रही है, वहीं केन्द्र सरकार के विज्ञापनों एवं पब्लिसिटी का खर्चा बढ़ता ही जा रहा है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजनाओं में भी पब्लिसिटी की जा रही है। महोदय, झारखंड सरकार के भी मनरेगा के अंतर्गत सामग्री मद में भुगतान हेतु लगभग 426 करोड़ रुपए लंबित हैं, जबकि झारखंड गरीब और पिछड़ा राज्य है। यह देश के अन्य राज्यों से नीचे दूसरे नम्बर पर है। यह पठारी इलाका है, बारिश के अलावा खेती-बाड़ी नहीं होती है। यहां पर ट्रैफिकिंग की समस्या है, पलायन और विस्थापन की समस्या है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मनरेगा के पैसे समय पर दिए जाएं।

महोदय, भारत सरकार की कोल कंपनियों द्वारा झारखंड में कोयले की रॉयल्टी के लगभग 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए लंबित हैं। ...(**समय की घंटी**)... माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बार-बार आग्रह करने के बावजूद अभी तक रॉयल्टी का पैसा नहीं दिया गया है, जबकि देश में कोयले की जितनी खपत है, उसका मैक्सिमम हिस्सा झारखंड से आता है। यह आर्थिक सौतेलापन क्यों है?

महोदय, पुरानी पेंशन व्यवस्था फिर से लागू की जाए, नहीं तो लोगों के बुढ़ापे की लाठी भी छिनती जा रही है। हमारी स्टेट में हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर दिया है और ऐसा हर स्टेट में होना चाहिए। राज्यों को जीएसटी संग्रह की देय राशि समय पर नहीं मिलती है। झारखंड जैसा गरीब राज्य भी इस वजह से आर्थिक परेशानी झेल रहा है। प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ हमारे राज्य में आठ लाख गरीबों को नहीं मिला है। यह लाभ भी उनको नहीं दिया

जा रहा है। गैर-भाजपा राज्यों के साथ आर्थिक मामलों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... 'सबका साथ, सबका विकास' सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए, धन्यवाद।

श्री उपसभापति : धन्यवाद। Now, Dr. Fauzia Khanji. Three minutes.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, there has been a lot of discussion on numbers and economic indicators since yesterday that measure the economic situation of our country. Perhaps, it is time for a recalibration of our matrix to ensure that the pursuit of progress is accurately reflected. Economic growth isn't just about numbers. There is a deeper narrative to explore. These numbers have to reflect on ground.

Sir, it is essential to move beyond surface level reporting. The most concerning issue this year is the escalating unemployment crisis in India, particularly, the dearth of Government job opportunities.

सर, मैं एक कवि की छोटी सी कविता पढ़ना चाहूंगी। जो बेरोजगारी पर है - "बेरोजगार"। यह देवी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई है।

" यह सवाल उसे शर्मिन्दा कर देता है,
कि क्या कर रहा है वह आजकल।
वह डकैती नहीं डालता, वह तस्करी नहीं करता,
वह हत्याएं नहीं करता, वह फरेबी के वादे नहीं करता,
वह देश नहीं चलाता है,
फिर भी यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि
क्या कर रहा है वह आजकल। "

†سر، میں ایک شاعر کی چھوٹی سی نظم پڑھنا چاہونگی۔ جو بے روزگاری پر ہے، ''بے روزگار''۔ یہ دیوی پرساد مشرا کی لکھی ہوئی ہے۔

یہ سوال اسے شرمندہ کردیتا ہے،
کہ کیا کررہا ہے وہ آج کل۔
وہ ڈکیتی نہیں ڈالتا، ہ تسکری نہیں کرتا،
یہ ہتیائیں نہیں کرتا، وہ فریبی کے وعدے نہیں کرتا،
وہ دیش نہیں چلاتا ہے،
پھر بھی یہ سوال اسے شرمندہ کردیتا ہے کہ
کیا کررہا ہے وہ آج کل۔

Mr. Deputy Chairman, unemployment is intertwined with alarming consequences notably with the rise in youth suicides. According to a report from Azim

† Transliteration in Urdu script.

Premji University, 42 per cent young graduates were unemployed. Sir, according to CMIE data, jobs in manufacturing dropped 31 per cent between 2016 and 2023. According to the latest report by the NCRB, over 13,000 students took their own lives in India in 2022; 9.6 of the suicides were those who were self-employed or salaried professionals. Unemployed persons comprise 9.2 per cent of all suicides reported in India. Graduates account for 5.2 of all suicide deaths. This dire scenario, Sir, often pushes vulnerable individuals towards extreme measures either towards an uptick in the use of drugs, petty crimes or suicides.

Sir, we understand that this Government has decided to put the number-system on fifth gear by relying on headline-friendly numbers turning the nation's progress into a clickbait economy. But, Sir, this is reducing complex issues to attention-grabbing figures and potentially overlooking the nuanced aspects of comprehensive development. Development is not about tall buildings or tall claims; it is about the quality of life that can never be measured in numbers. मैं एक कवि की दो पंक्तियाँ कहकर अपनी बात खत्म करूंगी। अगर गरीब और गरीब होता जा रहा है और धनवान और धनवान होता जा रहा है, तो मैं कहूंगी कि,

"मालूम करो हाथ उन्हीं का तो नहीं है,
जो लोग आग बुझाने में लगे हैं।"

माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

†**ڈاکٹر فوزیہ خان:** میں ایک شاعر کی دو لائنیں کہہ کر اپنی بات ختم کرونگی۔ اگر غریب اور غریب ہوتا جارہا ہے اور دھنوان اور دھنوان ہوتا جارہا ہے، تو میں کہوں گی کہ،

معلوم کرو ہاتھ انھیں کا تو نہیں ہے،
جو لوگ آگ بجھانے میں لگے ہیں۔

مانیئے اُپ سبھاپتی جی، آپ نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا ہے، اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Dr. Fauzia Khan. Now, Dr. M. Thambidurai; you have three minutes.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to participate in today's discussion on behalf of the AIADMK Party.

---

† Transliteration in Urdu script.

To begin with, it may be claimed that India is one of the fastest growing major economies of the world and that it is the sixth largest economy now. Since there is paucity of time, I would come straight to the subject. The GST plays its role in the country's economic development. We hear a lot from Members of different States here that the share of the GST pertaining to their State has not been given their due to which their economies were suffering. The Government must work out a mechanism to settle the issue immediately, without making the States suffer due to non-payment of GST share from the Centre.

Sir, as far as the erstwhile Government of Tamil Nadu is concerned, the AIADMK Government also suffered during that period. Hon. *Amma*, *Puratchi Thalaivi*, Dr. Jayalalita, and Edappadi Palanisamy, as Chief Ministers, faced financial constraints. Despite that, hon. *Amma* was able to implement many welfare measures like providing laptops and bicycles to students, through *Amma* canteens, *Amma* pharmacies, distributing gold *mangalsutras* to young women at the time of marriage, etc. During Shri Edappadi Palanisamy's term as Chief Minister, despite huge financial crisis, he also extended welfare programmes for farmers and efficiently tackled the situation during Covid period. He also extended financial assistance of Rs. 2,500 for each family during *Pongal* festival. He also ensured reservation of 7.5 per cent students from Government schools for admission into MBBS courses and also established 23 Medical Colleges for medical education.

As mentioned by many hon. Members yesterday, we support the demand for financial assistance by the present Government in Tamil Nadu to tackle the situation arising out of heavy rains and floods in Chennai, Thiruvallur and Kanchipuram due to Cyclone Michaung. When the earlier Government faced such a flood situation, the *Amma* Government and Edappadi Palanisamy Government tackled it very efficiently and took all possible measures. Also, I wish to state here that the present Chief Minister of Tamil Nadu said that while it was an artificially created situation earlier, the present one was a natural situation. I am unable to understand what Tamil Nadu Chief Minister mean by 'artificial situation'. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I would like to say here that the present DMK Government has failed to take adequate precautionary measures to tackle the rainflood situation in Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, confine yourself to the discussion on national economy. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, they spent Rs. 4,500 crores on drainage work. We fail to understand where the money has gone. ...*(Interruptions)*... Sir, the DMK Government needs to explain their inefficiency in tackling the rainflood situation in Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*... ...*(Time-bell rings)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, Tamil Nadu is in India. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I have got every right to speak about what the DMK Government is doing. ...*(Interruptions)*... The floods have created havoc in Tamil Nadu and people are suffering. Especially in Chennai, people are unable to move out. The present DMK Government has failed to tackle the situation. ...*(Interruptions)*... They want Rs. 5,000 crore from the Central Government. What happened to the Rs. 4,500 crore which was allocated for this ... ...*(Interruptions)*... They must explain where it has gone. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are discussing the national economy. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, flood rain water is not flowing there; it is liquour that is flowing throughout Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*... There is *ganja* flowing in Tamil Nadu. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... I am calling the next speaker. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, there is a lot of inefficiency in Tamil Nadu Government. That is what the Tamil Nadu Government is doing. ...*(Interruptions)*...Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The next speaker is hon. Ajit Kumar Bhuyan. You have three minutes. ...(*Interruptions*)... Nothing is going on record. ...(*Interruptions*)... Whatever Shri Ajit Kumar Bhuyan is speaking will go on record. ...(*Interruptions*)...

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN (Assam): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. Despite an impressive growth rate of 7.2 per cent in the current financial year ended by March, 2023, the demand side economy of the nation shows a very dismal picture. The demand for goods and services in India has been stagnant or declining due to various factors such as low income growth, high rate of inflation, massive unemployment and inequality in income and wealth. Some hon. Members were talking about employment. The views of the Members of the ruling party are a part of propaganda and are based on some lies. The unemployment rate for the country touches 3.2 per cent for the year 2022-23 as per the official Report published by the Centre for Monitoring Indian Economy. As per the NSO data, the rate of inflation in Indian economy is 5.02 per cent which is slightly declining from 6.83 per cent in August, 2023. Oxfam India's Report on 'Inequality in India', which is released recently, finds that 5 per cent of Indians own more than 60 per cent of the country's wealth. That is the reality. The extreme inequality in numbers has put the whole Indian economy in a situation of serious concern. In the list of World Happiness Index published by the United Nations Sustainable Development Solutions Network, India ranks at 126th position out of 150 countries for 2023. In accordance with the last HDI Report, India ranked at 132nd position out of 191 countries of the world. It is also a very serious concern for Indian economy that '2023 Global Hunger Index' gives India a rank of 111 out of 125 countries.

I am from Assam. So, let me speak a few words on Assam. If we consider the State of Assam, it is the 16th largest, 15th most populous and 26th most literal State out of 28 States of India. In terms of GDP, Assam's rank is 17th. It is Rs. 5.67 lakh crore. Approximately 32.07 per cent of Assam's population lives below the poverty line. As per the official statistics, Assam is India's 6th poorest State. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The next speaker is Shri Ramdas Athawale; not present. The next speaker is Shri Birendra Prasad Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Sir, today, world economy is suffering very seriously. At this critical time of world economy, we are discussing here the economic situation of our country. Countries like the United Kingdom and Germany are very seriously thinking about their economies. The Prime Minister of New Zealand

publicly announced inability to develop workforce and towards unemployment issue in New Zealand due to poor economic condition. But, at this critical juncture, India is making unprecedented historic economic development in our country under the leadership of the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi. Today, inflation is going down and the foreign exchange reserve in India is at an all time high. Infrastructure development is going on at a very fast pace in India. This is the reality of Indian economy today and this has been acknowledged by even the World Bank. In a recent report, the World Bank has stated that in this critical time that the world economy is facing, the Indian economy is doing very well. This is not my opinion. This is the opinion of the World Bank. Recently, they have published the Bulletin. In this Bulletin, the World Bank has recognised an unprecedented economic growth of our country. According to the World Bank's latest report titled 'India Development Update (IDU)', India continues to show resilience against the backdrop of a challenging global environment. It further states that India is growing at very fast pace and India has witnessed unprecedented expansion in its economy. As per the World Bank's half-yearly report, despite the significant global challenges, India emerged as one of the world's fastest growing major economies in the Financial Year 2022-23 with a growth rate of 7.3 per cent. India's growth rate was the second highest among the G-20 countries. Recently, we very successfully conducted the G-20 Summit in India, and India's rank is second among the G-20 countries in the matter of economic development. This is the present scenario of our country.

I would like to say one more thing. This resilience was underpinned by a robust domestic demand, strong public infrastructure investment and a strengthening financial sector. Bank credit growth increased to 15.8 per cent in the first quarter of the Financial Year 2023-24 when compared with 13.3 per cent in the first quarter of the Financial Year 2022-23. The Indian banking sector is working on a sound banking system. India follows the branch banking system and not the unit banking system as is followed in the USA. At a time when banks in major countries of the world are sinking and becoming financially bankrupt, the Indian banking system is doing very well and it has played a major role in the development of our country.

Then, many hon. Members have talked about inflation. It is agreed by everybody, and even when Shri P. Chidambaram was speaking yesterday, he also admitted that inflation rate, in the last three months, is going down like anything in our country. This is the real situation of our country. Before Independence, the per capita income of Assam was higher than that of other parts of the country. For a long time, when India was ruled by the Congress Party, the per capita income of Assam went down like anything.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Birendraji, please conclude. Your time is over.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: What is the reason? Why is the per capita income of Assam going down? I would like to say that this is due to the critical flood situation there. So, I appeal that in this strong financial position, the Government should show some positive intent to help Assam in dealing with the flood situation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: I would like to say just one more thing. In our economy, tea industry plays a very important role. In earning foreign exchange also, tea industry plays a major role. Now, the Indian tea industry, particularly in Assam and West Bengal, is facing serious challenge from the tea industries of Sri Lanka and Kenya. So, I would like to request the Government of India to come forward and help the tea industry of Assam for its growth and to face the challenged posed by the tea industries of Sri Lanka and Kenya. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Santanu Sen. You have nine minutes.

3.00 P.M.

DR. SANTANU SEN (West Bengal): Sir, before I come to the subject, I would like to strongly protest the pose and posture of one of our Cabinet Ministers targeting the only lady Chief Minister of the country just a few minutes back regarding one film festival. I can show you the video if you want. I strongly protest it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please come to the subject.

DR. SANTANU SEN: I am coming to the subject but it should be noted.

So far as economy is concerned, there are two pictures of Indian economy. One is the picture of privilege and the other picture is of the poverty. Sir, we live in India where six out of ten people survive on less than 260 rupees a day. So far as Global Hunger Index is concerned, out of 125 countries, it is very unfortunate to remind you that India ranks 111th. India witnesses thirty suicides a day due to poverty or unemployment. We live in India where, on the one hand, we talk about multi-trillion economy while, on the other hand, almost 550 lakh people are pushed into poverty due to healthcare cost and mainly due to out of pocket expenditure. At the

same time, you are targeting a few States by withholding the money for National Health Mission, which is depriving the common people of particularly-targeted States like West Bengal. It can be won over by political path. We live in India where it would take more than 200 years for a minimum wage worker in a rural area to earn what a top paid executive in an Indian company earns in a year.

So far as NREGA is concerned, it is very unfortunate that though a sizable Indian population depend on NREGA, in the last Budget, the budgetary allocation for NREGA has been curtailed by more than 33 per cent and we have heard our learned Prime Minister talking about NREGA when he said, यह तो माटी खोदने का काम है। We have seen in the Budget that it has been decreased. Sir, 154 farmers, daily wage earners and labourers commit suicide every day.

So far as NREGA is concerned, let me tell you that in our State of West Bengal, there are more than 21 lakh of people who have already done their job but they are still deprived of their wages for the last two consecutive years despite repeated, official and formal intimation. So many teams have come and in the name of investigation, they have made many excuses.

Let me give you a recent example. Let me share with you today's reply given in Lok Sabha regarding fake job card. Out of 7.4 lakh fake job cards found in the country as a whole, 3 lakh were from Uttar Pradesh, a State having double-engine *sarkar*; 1.15 lakh were from another State being run by an unofficial ally of BJP, that is, Odisha; and, 47,000 were found in another State being run by another friendly political party of BJP, that is, Andhra Pradesh. So far as West Bengal is concerned, it is only 5,000. So far as job card and Aadhar linking is concerned, West Bengal ranks second. In Andhra Pradesh, it is 99.7 per cent and in West Bengal, it is 99.68 per cent. Even then, Bengal is being deprived of its funds. Sir, 21 lakh people are getting deprived including one lady from Hoogly District, Nupar Hati, which was mentioned by our leader, Shri Derek O'Brien yesterday.

Sir, I was not here to raise the issue of gini coefficient but I have seen my colleague, a BJP Nominated Member, a renowned lawyer talking about the gini coefficient while addressing our Party leader, Derek O'Brien who does enough research before putting forward any fact or figure. Let me give you the facts. You were talking about gini coefficient targeting West Bengal. I will give you data of gini coefficient in the whole country. The Gini coefficient in India is forecast to amount to 0.35 in 2023. Number of people in India, who are earning less than 2 dollars per day is forecast to amount to 0.16 billion in 2023. This is for my beloved colleague. Sir, we live in India where we are having the maximum possible unemployment in the last 45 years. Per capita income in India is even less than one-fifth of that of China and less

than one-thirty two of that of the USA. We live in India where green curtains gracefully conceal the harsh truth that over 40 per cent of India's urban populace calls slums their homes. We can recall that day of Namaste Trump when a four feet wall was built just to conceal the actual scenario because the friend of learned Narendra Modi ji, Donald Trump, was supposed to visit our country. That is the harsh reality. Sir, in India, on November, 2016, we found demonetization. We know what its effect was and how the poor people suffered from this.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY) *in the Chair.*]

Sir, we live in India where 2 per cent of wealth tax on hundred billionaires can feed the children under the Mid Day Meal Programme for 3.5 years and where 3 per cent of wealth tax on the Indian billionaires can fund the National Health Mission for three years.

So far as the *Awas Yojana* is concerned, eleven lakh and thirty three thousand people are being deprived. Several teams visited our State of West Bengal in the name of national-level monitors, in the name of Central team. What did they do? Sixty-nine teams visited, Sir. Our Minister came on 7th November, 2022. Then, on 24th November, entire data was supposed to be given, and it was put on the portal in due course of time. Several enquiries were there. Action taken report was submitted in due course of time. Again, on 25th of November, questions were raised which were replied on 28th of November. But till date, no fund has come. Once again, on the 1st of December, another intimation has come to our Government of West Bengal that again 7 teams will visit 14 districts of our State of West Bengal. Why, Sir? Is it the only reason that it is being run by the Trinamool Congress, and Madam Mamata Benerjee cannot be defeated politically? Is it the only reason? Just tell me one State other than West Bengal which is being deprived in the same fashion. You can't.

Now, Sir, let me tell you India's external debt. It rises up to 629 billion dollars. The report given by the RBI in June, 2023 says this. Total debt per Indian over nine years has increased by 2.5 times. The outstanding debt on the Government of India was 55.87 lakh crore rupees on 31st March, 2014 and it has become 155.31 lakh crore rupees on 31st March, 2021, courtesy our BJP Government. Sir, every Indian has a loan which he has not taken. In 2014, the per capita loan was Rs. 43,214 and in 2023, it has become Rs. 1,09,373, courtesy our BJP Government.

Sir, let me tell you another fact. So far as houses are concerned, 63 per cent of women of India and 35 per cent of men don't have their own house. So far as cooperative federalism is concerned, it hardly exists in the recent scenario. We are

talking about the economy. Covid has unveiled the real scenario. We have seen the migrant labourers who were walking from one place to another. They were carrying their parents on their shoulders. Our Government has taken no step to solve the issues of these migrant labourers. *(Time-bell rings.)* Covid has shown the path, but unfortunately, our Government never takes any lesson from this incident. So far as the unemployment is concerned, Centre for Monitoring of Indian Economy speaks about unemployment. There is highest unemployment in the last 45 years. More than 40 lakh sanctioned Central Government posts are there. Around 30 lakh employees are there and more than 9.6 lakh posts are lying vacant till date. That is the real scenario of Indian unemployment. Unfortunately, so far as literacy is concerned, there is a tremendous gender disparity in literacy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude.

DR. SANTANU SEN: We don't know when Census will take place. Sir, just give me thirty seconds more. Sir, I will finish by saying that we are celebrating 75 years of Independence. We have two different ideas in India. And the story is called 'survival of the richest'. Let us strive for true equality and create a society where not a single individual is left behind.

My final comment will be this. We are very happy to take part in the Short Duration Discussion. Earlier it was for four hours. *(Time-bell rings.)* Now it has been extended for eight hours. We are really very happy. My two suggestions are: Why can't we have the same type of Short duration Discussion on Cooperative Federalism?

Lastly, I have got one question in my mind. If I can be satisfied by your reply..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Dr. Sen, please. I am sorry.

DR. SANTANU SEN: The Government is giving so much time for Short Duration Discussion. Are they not having any Business? That is the question in my mind. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Dr. Dinesh Sharma.

डा. दिनेश शर्मा (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी कृपापूर्वक अनुज्ञा से आज आर्थिक विषय पर मैं इस विद्वत समूह के समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत

की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। एक वह समय था, जब विदेश के लोग भारत की खराब छवि को प्रदर्शित करते थे और वृत्तचित्रों में उपहास उड़ाते हुए हम सब देख लेते थे कि कहीं गरीब, भूखा, नंगा और इस प्रकार की आवृत्ति वाला व्यक्ति, जो दीनहीन अवस्था में है, उसको भारत का नागरिक बताकर वृत्तचित्र में दिखाते थे। मोदी जी के आने के बाद जो नौ वर्ष का समय गुजरा है, उसमें आज वही भारत का नौजवान हाथ में कंप्यूटर लिए हुए जब विदेश में जाता है, तो अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को यह कहना पड़ता है कि इंडियन्स से बच कर रहो, कहीं ऐसा न हो कि ये हमारे देश के नौजवानों का रोज़गार छीन लें। मान्यवर, अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप बदला है, उसका मूल कारण यह रहा है कि क्रमागत तरीके से, एक विधिसम्मत तरीके से प्रत्येक बिंदु को छूने का प्रयास इस भारतवर्ष में नौ वर्षों से लगातार किया गया है। केन्द्र सरकार की जो भी योजनाएं थीं, उन योजनाओं का एक-दूसरे के साथ कनेक्शन रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधान मंत्री जी के द्वारा जब 'जन-धन योजना' की घोषणा की गई थी, तो लोग उपहास उड़ा रहे थे। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों में से केवल 25 लाख या 50 लाख लोगों के पास ही खाते हुआ करते थे, जबकि आज 55 करोड़ के आस-पास जन-धन के खाते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि अर्थव्यवस्था का बदलाव कैसे हुआ। आज जनधन खातों में लोगों के लिए यह जरूरी नहीं है कि एक निश्चित राशि को जमा करें, फिर भी हमारे देशवासियों का हौसला देखिए कि आज जो जनधन खातों में, जो ये 55 करोड़ खाते हैं, उनमें औसत 4 हज़ार रुपये जमा हैं।

हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से यह प्रगति हमारे देश में इस बात की परिचायक है कि हमने स्वदेशी को अपनाया, हमने उत्पादन को बढ़ाया। जहां तक लघु उद्योग की बात है, गांधी जी कहा करते थे कि हमें बहुत बड़ा उत्पादन नहीं, हमें बहुत लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए। आज हमने न केवल एमएसएमईज़ को बढ़ाया है, हमने न केवल करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन देकर उद्यमी के रूप में परिलक्षित किया, बल्कि हमने स्टार्टअप के माध्यम से, मेक इन इंडिया, स्टैण्डअप इंडिया और डिजिटल इंडिया के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप में रोजगारों के सृजन की प्रक्रिया को तेज किया है। मान्यवर, आज भारत एक तेज विकास गति से बढ़ने वाला देश बना है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था ने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को बढ़ाया है। आज यह देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि इन नौ वर्षों में हम भारत के हर गांव में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के बिल्कुल निकट पहुंचे हैं। यह देश महिला, युवा, किसान, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित लोगों का देश बन चुका है। आपके संज्ञान में यह लाना जरूरी है कि आज सरकार के समावेशी प्रयासों के माध्यम से सरकार ने साढ़े तेरह करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। आज 'पीएम किसान' सहित कई योजनाओं के माध्यम से अन्नदाता को बड़े पैमाने में सशक्त करने का प्रयोजन चल रहा है। देशभर में चल रहे रोजगार मेले ने बहुत सारे रोजगार पैदा किए हैं। आज भारत रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी का कलेक्शन कर रहा है। कृषि उत्पादन के मामले में आज नित्य नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। मान्यवर, यह वह भारत है, जहां पर करों का भार पड़ा करता था। सत्रह-सत्रह करों का समावेशन करने के बाद उनका सरलीकरण किया गया। आज कई गुना, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पचासों गुना ज्यादा करों का जो संग्रह है, उस संग्रह ने आज पूरे भारतवर्ष को यह दिखाया है कि भारत याची नहीं है। भारत वह देश नहीं है, जहां कांग्रेस के शासनकाल में जरूरत पड़ने पर अमेरिका से सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं आता था और यहां आने के बाद राशन कार्ड द्वारा वह लोगों को बंटता था। वह लाल रंग का गेहूं वहां के जानवर

नहीं खाते थे, तो वह हिंदुस्तान के लिए भेजा जाता था। आज इस देश में आप देखें, तो पांच किलो अन्न ढाई वर्षों से, कोरोना के बाद भी आज मुफ्त में देने का काम किया जा रहा है। इसके कारण आज यहां गरीबी रेखा से ऊपर उठने का क्रम सतत जारी है।

मान्यवर, best credit-rating agency S&P Global के अनुसार, भारत 2030 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज हम यह कहते हैं कि हम पांचवीं अर्थव्यवस्था हैं। हालांकि पहले हम अर्थव्यवस्था में दसवें नम्बर पर थे या उससे पहले ग्यारहवें नम्बर पर थे, जबकि आज हम पांचवीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस पांचवीं अर्थव्यवस्था के बनने के पीछे मैं यह कह सकता हूं कि जिसे हम purchasing power parity (PPP) बोलते हैं, उसका अगर आकलन किया जाए, तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसरित हो चुका है। आज भारत का नागरिक जब विदेशों में जाता है, तो वह सिर उठाकर देख सकता है और मैं यह कह सकता हूं कि हमारा जीडीपी, जो पिछली तिमाही में 7.6 परसेंट हुआ है, उसने भी बहुत लोगों को चौंकाया है। आज चीन मुद्रास्फीति के कारण कराह रहा है, आज जर्मनी मुद्रास्फीति के कारण अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचा है, आज अमेरिका में हलचल मची हुई है और ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए प्रधान मंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है और आखिर में स्थिरता आ सके, इसके लिए एक सनातनी को लाकर प्रधान मंत्री बनाना पड़ता है और जब सनातनी आता है, तो वह वहां की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का काम करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यह भारतवर्ष है, जिसका जीडीपी आगे बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो गया है, जबकि वैश्विक दर 3 प्रतिशत के आस-पास है। आज आईएमएफ भारत की सराहना कर रहा है और चीन की ग्रेडिंग कम कर रहा है। आज भारत विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में जी20 में उभरकर आया। उसका मूल कारण यह था कि हमारा उत्पादन बढ़ा है। हमने उपभोक्ता के अनुसार डिमांड को क्रिएट किया है, आज हमारा ट्रेड बैलेंस फेवर में हुआ है। आज निर्यात संवर्धन की नीति पांव पसार रही है, आज आयात कम हुए हैं, आज स्वदेशी के कारण हमारा जो उत्पादन है, उसकी लागत प्रति इकाई कम होती जा रही है। यही वजह है कि भारत आज ऐसा भारत बना है। लोग व्याख्या कर रहे थे कि बंगाल में जी डी पी 8.5 परसेंट है। बंगाल तो पहले से समृद्ध प्रदेश हुआ करता था। अंग्रेज जब सोने की चिड़िया समझकर हिंदुस्तान में आए थे, तो सबसे पहले वे आर्थिक राजधानी के रूप में बंगाल में गए थे। बंगाल में जब विभिन्न प्रकार के शासन आए, तो क्रमागत रूप में उनकी आर्थिक व्यवस्था का ह्रास होता गया। एक समय रोजगार के लिए लोग कहीं जाते थे, तो वे बंगाल जाया करते थे। मुझे खुशी है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं। कोरोना के काल में तमाम लोग वापस उत्तर प्रदेश आए। उनको उत्तर प्रदेश में रोजगार मिला। आज बंगाल के लोगों को रोजगार खोजने के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज की बदलती हुई स्थिति में 13.5 करोड़ लोगों को हमारी सरकार ने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है और 'पीएम किसान सम्मान नीधि' जैसी योजनाओं ने अन्नदाताओं को बड़े पैमाने पर सशक्त किया है। रोजगार मेलों के माध्यम से आज रोजगारों का सृजन हुआ है। केवल नौकरी देने से रोजगार नहीं होता है। हम अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार देते हैं। हम नौकरी भी देते हैं और स्टार्ट-अप से नौकरी को क्रिएट भी करते हैं। हम विभिन्न प्रकार के पूंजी निवेश को बढ़ाते हैं। हम सोना नहीं बेचते हैं, बल्कि हम अपनी निधि का सृजन स्वयं किया करते हैं। आज अगर आप देखें तो निरंतर बढ़ते हुए जो UPI transactions हैं, उनसे डिजिटलीकरण के प्रतीक के रूप में भारत नित्य नए शिखरों को छू रहा है। अभी हमने त्योहार

मनाया, दीवाली मनाई। हालांकि पहले जब हम त्योहार मनाते थे, तो हमारे उत्तर प्रदेश में curfew लगा करते थे कि दीवाली आई तो curfew, ईद आई तो curfew, लेकिन अब की दीवाली में पूरे देश ने चार लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यवसाय किया है। यह भारत की समृद्धता की ओर बढ़ने का एक कदम है। लोग बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो वह काशी के विश्वनाथ बाबा का ज़िक्र करती है, वह मथुरा का ज़िक्र करती है, वह अयोध्या का ज़िक्र करती है, लेकिन मोदी जी की सोच देखिए कि आज धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद कई गुणा लोग वाराणसी में आने लगे हैं। आज कई लाख लोग अयोध्या में आ रहे हैं, जहां पर श्री रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। धार्मिक आस्था का सम्मान और साथ में आर्थिक समृद्धि का भी आयाम प्राप्त हो, यह नीति केवल उसी की हो सकती है, जो निष्पक्षता के भाव से काम करे।

मान्यवर, आज जो वैश्विक रेटिंग हुई है, उसमें 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में कहा गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, economic power बनेगी, वह 2027 तक बनेगी। भारतवर्ष में मोदी जी मुद्रा योजना लेकर आए और आज आठ करोड़ लोग इसके कारण उद्यमी बन चुके हैं। आप लोग रोजगार सृजन की बात कहते हैं। मैं आपको रोजगार सृजन की बात बताना चाहता हूं कि 2014 में केवल 350 startups थे और आज 1,25,000 startups हैं और 110 से ज्यादा unicorns active हैं। हमारे देश में लोगों की औसत आय भी बढ़ी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयकर विभाग के जो आंकड़े हैं, उन्होंने यह बताया है कि 2014 में औसत आय 4 लाख रुपए थी, आज यह 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। अगर यह विश्लेषण नहीं होता तो यह आय कैसे बढ़ती, कहां से पैसा आया। जो overhead expenditures थे, जो उपरिव्यय थे, उन पर रोक लगाई गई, जो भ्रष्टाचार था, उस पर रोक लगाई गई और उन पर रोक लगाने के बाद जो पैसा आया, वह जनता का पैसा, जनता के खातों में पहुंचाया गया। यह मोदी नीति है और इस मोदी नीति के कारण आज जो बदला हुआ परिदृश्य है, उसमें आज IITs खुल रहे हैं, आज IIMs खुल रहे हैं, आज medical colleges खुल रहे हैं। आज यह साम्प्रदायिक दंगों वाला प्रदेश नहीं है, आज यह सनातनियों का विरोध करने वाला देश नहीं है, कुछ जगह पर लोग हो सकते हैं, लेकिन पूरा देश नहीं है। आज यह देश का सम्मान बढ़ाने वाला देश है। यह अब सोने की चिड़िया नहीं रहा है-- पहले हमारा देश सोने की चिड़िया होता था, विदेशी आते थे और पंख उखाड़ कर चले जाते थे-- अब यह सोने का दहाड़ता हुआ शेर वाला देश बना है। यह मोदी के स्वप्नों का देश है और यह आर्थिक सम्पन्नता की ओर जाने वाला देश है। मान्यवर, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि रोजगार कैसे बढ़ता है। आज से 9 साल पहले खादी ग्रामोद्योग में केवल 25-30 हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय था, जबकि आज 1,30,000 करोड़ से ज्यादा का स्वदेशी उत्पाद बढ़ चुका है। यह स्वदेशीकरण की जो प्रक्रिया है, उसके कारण अब भारत हथियारों को खरीदने वाला देश नहीं है, अब हथियारों की supply करने वाला देश भी बन गया है। अगर आप देखें, तो भारत ने 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात किया है। पिछली सरकारों के मुकाबले भारत का आर्थिक स्वाबलंबन कई गुना बढ़ा है। आज मोबाइल के क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में नम्बर दो पर बना हुआ है।

मान्यवर, जब मैं उत्तर प्रदेश में उपमुख्यमंत्री था, तब IT मंत्रालय मेरे पास था। मैंने देखा कि कोरोना के समय चीन से कम्पनियां भाग रही थीं, तो वे वियतनाम नहीं जा रही थीं, वे कोरिया

नहीं जा रही थीं, वे हिन्दुस्तान में आ रही थीं और हिन्दुस्तान में भी वे उत्तर प्रदेश में आ रही थीं। अगर आज 100 मोबाइल्स बनते हैं, तो 65 मोबाइल्स उत्तर प्रदेश में बनते हैं और उसके उपकरण भी उत्तर प्रदेश में बनते हैं। यह बदलते हुए भारत का स्वरूप है। यह मोदी जी का निष्पक्ष भाव से, समर्पण भाव से अर्थव्यवस्था को ठीक करने का जो चक्र था, उसके कारण हुआ है। आज उपभोग साल दर साल बढ़ रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष digital transaction की संख्या 61 फीसदी और digital transaction की राशि में 47 फीसदी की वृद्धि हुई है। यही नया भारत है। यह नव भारत का उत्थान है। यह वह भारत नहीं है, जो कटोरा लेकर भीख मांगने जाएगा। हम याची नहीं हैं, अब हम दाता बन गए हैं। यह वही भारत है कि जब यहां पर एड्स होता था, मलेरिया होता था, डेंगू होता था, तो हमारा देश दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाता था कि टीका दे दो, टीका दे दो। कई गुणा दामों पर वह टीका, वह वैक्सीन हिन्दुस्तान को मिला करती थी और सालों बीत जाते थे तथा हजारों, लाखों लोग मर जाते थे। यहां पर कोरोना आया। इससे पूरा विश्व प्रभावित रहा और दसियों लाख लोगों की मृत्यु अमेरिका जैसी जगह पर हुई। भारत में तीन-तीन वैक्सीन्स बनीं और 120 देशों को वैक्सीन सप्लाई करने का काम किया गया।

मान्यवर, यह बढ़ता हुआ देश है और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि लोग अमेरिकन डॉलर, यह डॉलर, वह डॉलर का उल्लेख करते थे, लेकिन आज जब से भारत जी20 का सिरमौर बनकर आया है, 18 देशों में रुपये में ट्रांजेक्शन होने लगा है। मान्यवर, भारत की मुद्रा बढ़ रही है, भारत का अस्तित्व बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी)स्कीम है, उसकी वजह से अब कोई कहने वाला नहीं है कि 100 रुपये भेजते हैं, 85 रुपये का गबन हो जाता है और केवल 15 रुपये ही पहुंचते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से जो 100 रुपये भेजते हैं, वे 100 के 100 रुपये आज जनता के खाते में पहुंचते हैं।

मान्यवर, यह बदलता हुआ भारत है और मैं इस बदलते हुए भारत में कह सकता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न का भी एक डेटा आया है। उस डेटा से यह पता चलता है कि विभिन्न आय वर्गों में टैक्स बेस बढ़ा है। हर वर्ग में टैक्स फाइलिंग में कम से कम तीन गुना वृद्धि हुई है। मान्यवर , यह पारदर्शिता है, यह ईमानदारी है, यह स्वेच्छाचारिता से काम करने की प्रवृत्ति का परिणाम है कि लोग आज स्वेच्छा से कर देने के लिए आगे आए हैं। ..(**समय की घंटी**).. मान्यवर, मैं एक अनुरोध करूंगा कि आज आपने मुझे पहली बार इस विद्वत समूह में बोलने का सुअवसर प्रदान किया है, अतः मेरी आपसे यह अपेक्षा है कि आप मुझे कुछ समय देंगे। क्योंकि मैं पहली बार बोल रहा हूं, इसलिए मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे थोड़ा समय देंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेंदु शेखर रॉय) : मेरे हाथ बंधे हैं। जो टाइम एलॉट किया गया है, आपको उसी के हिसाब से बोलना है।

डा. दिनेश शर्मा : मान्यवर, मैं पहली बार बोल रहा हूं, इसलिए मुझे benefit दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेंदु शेखर रॉय) : आपको पंद्रह मिनट दे दिए हैं, आप एक मिनट और बोल लीजिए। Please. *...(Interruptions)...* Please. *...(Interruptions)...*

डा. दिनेश शर्मा : मान्यवर, मैं यह कह सकता हूं कि आज पूरा भारतवर्ष जिस तेजी से विकसित हुआ है, उसके कारण आज भारतवर्ष में लोगों की भावना बढ़ी है। उन्होंने भारत के बारे में कहा है कि केवल यह वर्ष भारत का नहीं है बल्कि यह सदी भारत की होने वाली है, यह सदी भारत की है। यह भारत अर्थव्यवस्था के मामले में सुदृढ़ होगा, आत्मनिर्भर होगा और विश्व का नेतृत्व करने वाला होगा।

मान्यवर, मैं आखिर में सम्मानित विपक्ष से एक बात कहूंगा। मैं बहुत सपने संजोकर आया था कि मैं विद्वतजनों के समूह में बोलने का अवसर पाऊंगा। यहाँ विद्वतजन हैं भी, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे फुटबॉल का मैच होता है, उसमें आप देखते हैं कि रेफरी भी दौड़ता है और फुटबॉल के खिलाड़ी भी दौड़ते हैं, लेकिन दोनों में एक अंतर होता है। खिलाड़ी गोल करने के लिए दौड़ते हैं और रेफरी गलती निकालने के लिए दौड़ता है। मैंने देखा कि विपक्ष की भूमिका रेफरी की भूमिका बनी है। यदि रेफरी भी नकारात्मक भूमिका में आ जाए, तो निश्चित रूप से गलत तथ्यों के प्रस्तुतिकरण से समस्या होती है। इस सरकार की एक सकारात्मक दृष्टि है, इसलिए मैं आह्वान करूंगा कि विपक्ष आगे बढ़कर आए और मोदी जी के सुशासन में एक सहभागी बने। आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनकर इस भारत राष्ट्र की संप्रभुता, जो पूरे विश्व का सिरमौर बनने के लिए अग्रसरित है, उसमें उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है ,इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेंदु शेखर रॉय) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भाषण बहुत ही जोशीला था। Now, Shrimati Jebi Mather Hisham.

SHRI JEBI MATHER HISHAM (Kerala): Sir, I thank the Congress Party, Congress President, Shri Mallikarjun Khargeji, CPP Chairperson, Shrimati Sonia Gandhiji, Shri Rahul Gandhiji and CPP leadership for giving me this opportunity to make my maiden speech here in this august House, especially, on the important topic of the state of economy of our nation. Today, we are at the very end of the second term of BJP Government. We have had nearly ten years of BJP and Modiji's rule. Our hon. Prime Minister loves to compare Congress Party's 60 years of governance with his 10 years. In 60 years of Congress rule led by Nehruji to Shri Manmohan Singhji, our nation grew from the depth of a resource-starved economy which the British left us with, at the time of Independence, in 2014 to become one of the tenth largest economies of the world and having built the foundation and springboard to grow further. With this strong foundation laid by the Congress Party, our nation's economy has grown naturally since Independence and after 2014 also. However, the face of growth, which is claimed by BJP Government, is also under the clouds of suspicion as several indicators such as poverty, unemployment, health on the ground, point to the contrary. More importantly, at what cost has this growth been claimed by BJP

Government since BJP came to power? This is an important question for us to decipher the cost of this growth claimed by BJP Government that our nation has had to pay since BJP Government came to power.

Sir, let me put forth a few important points in this regard. First, our nation's debt which stood at Rs.58.60 lakh crore, that is, 52.20 per cent of GDP as on 31st March, 2014, today, is Rs.155.60 lakh crore, that is, 57.10 per cent of GDP. It means that the debt on every Indian has increased by 2.53 times in the last nine plus years. The astronomical increase in the Government's debt due to the Modinomics means that each Indian today has a debt, I mean, India's per capita debt today is Rs. 1,09,373 compared to Rs.43,124 in 2014. I very respectfully ask our Prime Minister as to what is your answer to adding debt of Rs.66,249 in ten years of your Government *versus* Rs.43,124 in sixty years of Congress Government on to the shoulders of every Indian in your ten years of heading the Government.

Secondly, our nation had an unemployment rate of 4.90 percentage in the financial year 2013-14 when Congress Party was in power. The unemployment rate, this financial year, is hovering around 7.90 percentage plus. I very respectfully ask our Prime Minister as to what is your answer to the unemployment rate in our nation almost doubling in your ten year term of heading the Government.

Thirdly, India's ranking in Global Hunger Index was 55 in 2014. Today, India's ranking in the Global Hunger Index is 111 out of the 125 countries with sufficient data to calculate Global Hunger Index scores. I very respectfully ask our Prime Minister as to what is your answer to the ranking of the Global Hunger Index of our nation falling from 55 to 111 in your ten years term of heading the Government.

Fourthly, India's ranking in the World Economic Forum - Annual Gender Gap Report was 114 in 2014 and, today, India's ranking in the World Economic Forum - Annual Gender Gap Report is 127. I very respectfully ask our Prime Minister as to what is your answer to the ranking of the World Economic Forum - Annual Gender Gap Report of our nation falling from 114 to 117 in your ten years term of heading the Government.

Fifthly, as per the World Inequality Report 2022, the average household wealth in India today is around Rs.9,83,010. The bottom 50 per cent of the nation can be seen to own almost nothing with an average wealth of Rs.66,280 per household or 6 per cent of the total wealth of the nation. The middle class is relatively poor with an average wealth of Rs.7,23,930 per household or 29.50 percentage of the total wealth of the nation. The top 10 per cent household owns 65 per cent of the nation wealth averaging to Rs.63,54,070 per household. The top one per cent household owns 33 per cent of the nation's wealth averaging Rs 3,24,49,360. I very respectfully ask our

Prime Minister: What is your answer to the status of our nation as one of the most unequal countries in the world with rising poverty and an affluent elite in your 10 years term of heading the Government? Sixth, reducing fuel prices was very dear to our Prime Minister during the 2014 election campaign. Obviously, fuel prices hit at the root of an economy and more so Indian economy. However, from 2014 to 2023, petrol price increased from Rs 72.26 per litre to Rs.100 plus per litre and diesel price from Rs 55.49 per litre to Rs.90 plus per litre between 2014 and 2023. Similar is the case with kerosene and LPG too. This, despite petroleum crude prices being exorbitantly high during 2014 versus the subsidized petroleum crude, which we are getting from Russia since the Ukraine war. I very respectfully ask our Prime Minister: What is your answer to the huge increase in the prices of petrol, diesel, kerosene and LPG, in your 10 years term of heading the Government? Most importantly, Indian rupees exchange rate with the US dollar on 31st March 2014 was Rs 59.90. The rupees exchange rate is by self-admission, a matter very close to our Prime Minister's heart. Yesterday, Indian rupees exchange rate with US dollar fell to Rs 83.41, the lowest ever in the history of our country. I respectfully ask our Prime Minister: What is your answer to the Indian rupee depreciating to its lowest ever rate in your 10 years term of heading the Government? Eighth, in 60 years, Congress Government built world-class infrastructure from effectively nothing in 1947. Today, the Government under the National Monetization Pipeline is selling these national assets valued at an estimated Rs 6 lakh crore in public sector one by one to private sector, enriching the favourite friends of the BJP. I very respectfully ask the Prime Minister: What is your answer to your Government handing over national assets to your favourite friends in your 10 years term of heading the Government? I quote our first Prime Minister, Pt. Jawaharlal Nehru*ji* who our present Government attacks for all issues they cannot find solutions for and for mistakes they cannot defend. Pt. Jawaharlal Nehru*ji* said, 'Facts are facts and will not disappear on account of your likes'. I can go on and on about various factors and statistics connected to the dismal state of economy from inflation to price rise, to MGNREGA state to skill India to Beti Bachao Beti Padhao, and so on and so forth. Of course, then my senior colleagues from the Treasury Benches will ask few pointed questions. First question they ask would be, is the economy not growing? And our answer is serious questions remain on the reality of the growth claimed by the BJP Government as the economy is exhibiting several contra-indicators to the claims of BJP Government. Another question which they ask would be is, is FDI not coming to India, and what we wish to say is that it is only natural that FDI come to India based on the open door liberalised regime initiated by the Congress Government and the reality that MNCs cannot ignore a market as large as India for

which the stage was set by the Congress Party. Yet another question, the chest-thumping question would be, did we not win the recent State elections? My senior colleagues from the Treasury Benches, almost all of them have said that and we wish to say you did win. But, very few media has reported that more Indian citizens '*humare deshwasi*' voted for Congress party than BJP. About 11 lakh more Indians voted for Congress party where BJP polled 4.81 crores votes, Congress party polled 4.92 crore votes. So, we the Congress Party, has been in the heart of India for 138 years and we, the Congress Party, is in the heart of India now despite you wishing us away and we, the Congress Party will remain in the heart of India despite you wishing for '*Congress Mukt Bharat*'. We will continue to oppose your wrongdoings and we will continue to expose your *jumlas*. Our India is great, we will work to make her even greater and the greatest in the world. Jai Hind!

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): The next speaker is Shri Sircar; your time is five minutes.

SHRI JAWHAR SIRCAR (West Bengal): Sir, Mr. Jethmalani, before me, has described * as big * white * and statistics. There is a fourth category of * that I would like to bring to your attention.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Mr. Sircar, one minute, the word * is not allowed in the Parliament. It is expunged.

SHRI JAWHAR SIRCAR: Sir, I modify it, but to the extent that I would like my friends in the House on both sides to be aware of the realities. They keep talking about GDP growth. I would not contest it, because it is too complicated for many to understand. But what does GDP growth mean where I am concerned and you are concerned, that is, per capita GDP, per person GDP. The GDP of Ambani and GDP of Adani does not matter to me. We just had the G-20 meeting and there we made a calculation that the US has 63000 dollars by way of their per capita GDP, Australia has 61000 dollars, Indonesia has 4000 dollars plus per person and India is the lowest, I repeat India is lowest among the group, we have just 2085 dollars per GDP. So, look at reality, do not go in for bravado and bragging. When you talk of GDP, you must remember that you are taking the wealth of the upper five per cent to inflate your figures. I have just

*Expunged as ordered by the Chair.

given the example of how the upper crust has increased its wealth. The Ambani wealth was Rs. 1.6 lakh crores in 2014, I repeat Rs. 1.6 lakh crores in 2014. It is Rs. 8.6 lakh crores today, five times more. Please show me an Indian who has grown his income in the last nine years by five times before you make further statements. Adani's went up from Rs. 1.2 lakh crores, this is more phenomenal, but, I will not get into the details. From Rs. 1.2 lakh crores, they have gone up to Rs. 6 lakh crores plus which is again another five times growth. No Indian has ever grown at this rate during the last nine years. So, don't take credit for enriching the oligarchs, don't take credit for enriching and fattening the capitalist class and then say, "we grew as a whole". Now look at your reality. World Bank's unemployment figures, I am quoting from the World Bank because most Indians and foreigners have given up on Indian statistics. It is so punctuated with untruths. The World Bank's 2022 unemployment rate it shows that in India there is 23.2 per cent unemployment. Compare it with Pakistan, a failed state, Pakistan is 11 per cent, less than half; compare it with Bangladesh, once upon a time a basket case, Bangladesh is 13 per cent and we are 23 per cent. Bhutan is 14.9 per cent. So, where are the realities that you are drum drumming about GDP and becoming the fourth biggest and the third biggest in the world? Come to reality. We have the annual survey of industries pointing out that we are steadily moving towards contractual labour. We are turning a rightful, respectful wage earner into a product that is at the mercy of employer so far as labour timing and everything is concerned. I come to the labour participation ratio. The labour participation ratio - the Labour Minister was here, but does not seem to be unduly interested -- the LFPR in India is one of the worst in the world. I repeat at the cost of perjury, one of the worst in the world. 42 to 45 per cent was the participation of labour. That means the vast majority was outside the network of labour. Mercifully, it has gone up to 50 per cent now. 50 per cent! But look at the other countries; Nepal 83 per cent. Nepal is able to provide labour force participation of 83 per cent; again, Bangladesh, twice more, China 60 per cent. What are we talking about? (*Time-bell rings.*) This much, of course, relates to the female labour participation ratio, where I repeat the figure, India is only 20.5 per cent, Nepal 83 per cent, Bangladesh 30 plus per cent, China 60 per cent and even Sri Lanka that was on the verge of collapse, they have a female labour participation of one-and-a-half times of ours. When it comes to male and female combined, we have been 42 and 45 per cent during the entire regime of the last nine years.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Please conclude, now.

SHRI JAWHAR SIRCAR: I repeat 42 to 45 per cent, one of the lowest in the world. It has just gone up to 50 per cent. We look at gender gap. Jebi already mentioned about the gender gap. I repeat that compare the gender gap of India at 28 per cent with double that in Bangladesh. She also mentioned about the rising debt. I repeat public debt is increasing at a phenomenal rate as we are binding future generations, your grandsons, your sons, my sons and my grandsons to a debt that we are not entitled to.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Thank you, Mr. Sircar. Your time is over.

SHRI JAWHAR SIRCAR: One more minute, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): One more minute I have already given to you. ...*(Interruptions)*..

SHRI JAWHAR SIRCAR: Debt ratio has come to almost 90 per cent. Sir, just one last word, one last word on defaulters, on banks, just one word; we were coming around to the banks, defaults of the banks and there yesterday's figures, that is why I am giving it to the House, is 14.5 lakh crores of rupees have been written off. Dr. Karad is sitting there. He insists that writing off means nothing, but I insist that writing off is actually the legitimization of the destruction of your funds, my funds kept with the banks. (*Time-bell rings*) The corporate sector .. *(Time-bell rings)*... I will give the calculations.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): I will have to call the next speaker. ...*(Interruptions)*..

SHRI JAWHAR SIRCAR: Thanks to the cooperation, thanks to the transparent reply given by Dr. Karad and others, the corporate sector alone has liquated ten lakh crores rupees in nine years. Sir, Rs. 10 lakh crores have gone down the drain to save the corporate sector! Whereas, NREGA — hon. Minister is sitting somewhere here who alone has ...(*Interruptions*)...*

*Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): No, no. Please stop. Mr. Wilson, please start.

SHRI P. WILSON: Sir, don't deduct it from my time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Mr. Wilson, please start. It is not being recorded.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, a lot of discussion has taken place in this august House. My previous speakers have talked about how economic condition of our country has deteriorated. I wanted to point out a few. When you came to power in 2014 and re-elected in 2019, what did you promise? Did you implement these promises? I remind you some of the promises you have made. You said that you will reduce price of LPG, petrol and diesel. You promised Rs. 15 lakhs in bank account of each citizen of this country. What happened to the same? You promised that you will link sixty rivers with an estimated cost of Rs. 5.5 lakh crores. What has happened to that? You promised US$ 5 trillion economy in 2019 to win over for the second time. What is the economy today? In 2016, you promised doubling farmers' income by 2022. What has happened to it? You promised cleaning of Ganga. You promised inland waterway transport system. You promised 2 crore jobs and controlling prices. These have all been reduced to mere words. Today, Sir, more than 10 lakh vacancies have been registered on the National Career Service Portal. What steps have you taken to fill these vacancies? There is a failure in Make-in-India, StartUp India, demonetization and GST regime. These policies have weakened the institutions and the economy. And, these are the shining examples as to how today's economy is.

Sir, Tamil Nadu is the 10th largest State in India, is the 2nd wealthiest State in terms of GDP and is the 2nd largest contributor to India's GDP. For every rupee that Tamil Nadu contributes to the Centre, it gets only twenty-nine paise! This demonstrates the immense contribution made by our State. But, what is the return it is getting? Today, I will dwell into the step-motherly treatment which my State is facing in the hands of the Union Government. However, the present Government has been helping their corporate friends to earn humongous profits and showering non-existent promises to the citizens of the country! Sir, I wanted to ask a question. Has the per-capita income of every Indian citizen increased? Sir, villages are the worst affected. There is no agriculture. There is no industrial growth. There are no jobs.

The daily-wagers, low income workers are the sufferers because of rise in prices of essential commodities and leading a miserable life.

You have sold all the public sector undertakings in the country. The business owners have also been adversely affected by the rise in prices of essential commodities as they have not been able to cope with the rising prices and have also not been able to get rise in the price of their finished goods which makes it difficult for them to survive in this competitive world. Sir, first of all, I wanted to place how our State is meted out step-motherly treatment. Sir, there are 17 projects floated in Tamil Nadu by NHAI. About eleven projects are pending for more than three years because of non-allocation of necessary funds. The Ministry of Statistics and Programme Implementation had itself, on 12th September 2023, uploaded on its website that 42 projects in Tamil Nadu -- that too important projects, including nuclear projects — are delayed.

Sir, my friend was talking about Corona and how it was dealt with. In Tamil Nadu, we have a Vaccine Park in Chengalpattu district. It was established at the cost of Rs. 2000 crores. The Government of Tamil Nadu has given vast lands for it. Right from the day one, when the Vaccine Park came into existence, not even one vial has been manufactured there because they wanted to promote some private players and they kept it closed for many years despite the Chief Minister's request during Covid times to hand over that to them so that they can manufacture vaccines and supply to the entire country. But the Centre showed deaf ears. They refused to budge.

Insofar as Railway projects are concerned, we have a body building factory, that is, the Integral Coach Factory in Avadi. Many rail coaches have been manufactured by this Integral Coach Factory. But, today, the sad state of affairs is that they are going to other countries and purchasing coaches, ignoring the factory that is already available in Tamil Nadu. In Chennai Metro Rail Projects, Phase-II projects are pending with the Cabinet Committee of Economic Affairs. The clearance is not being given for the last two years, despite repeated requests.

So far as the Food Corporation of India is concerned, the subsidy of Rs. 6,500 crores for the PDS rice has not been disbursed to Tamil Nadu. Likewise, the CMR subsidy of Rs. 5,704.09 crores has not been disbursed to Tamil Nadu. In CMRL, 50:50 equity share requested, similar to phase I, is pending with the Government of India for Cabinet approval.

So far as Election Commission expenses are concerned, Rs. 213 crores are pending. Similar is the case with Home Guards. Sir, Rs. 77.76 crores are pending.

In Tamil Nadu, we have the highest number of toll plazas. There are about 55 toll plazas in each and every nook and corner. As per the Act, you should have one

toll plaza at every sixty kilometres. There are about sixteen excess toll plazas in Tamil Nadu. All the money, which is collected by these toll plazas, is not being utilized for road infrastructure in Tamil Nadu. Still, it is drained out. The saddest thing is that toll fee is increased every year without any application of mind. There is one stretch about which even our Chief Minister called the Road Highways Minister and said that that stretch needed immediate attention. But sadly, even after a lapse of six months, the stretch, which is in Vellore, is yet to be repaired.

So far as sugarcane growers are concerned, they are selling their yields to the mill owners. But, no price has been paid for their yields for the last five years. The mill owners are getting protection. That's why they are not making payments to farmers.

So far as spinning mills are concerned, they are incurring heavy losses because of the increase in the prices of raw materials, high inflation, and slowdown in the global economy. In fact, our Chief Minister has written a letter requesting the Union Government to provide financial support for MSMEs in textile sector, to restructure the existing loans under Emergency Credit Land Guarantee Scheme and to disburse fresh loans under ECLGS by reducing regular interest to offset losses.

We have recently faced cyclone. For four days we had very heavy rainfall.

4.00 **P.M.**

Even today, we are receiving heavy rainfall. In fact, our Chief Minister has demanded a sum of Rs.5,000 crores as an interim financial assistance. I only request my good friends to see that the said financial assistance is sanctioned and disbursed immediately. One thing I have to bring to your attention. Sir, you are also a learned Member of our fraternity. They have brought the Insolvency and Banruptcy Code, 2016. This law has been legislated for the industrial friends who want to acquire industry. Under the garb of legal procedure, they are liquidating many industries. The principles such as waterfall mechanism, clean-slate theory, hair-cut, write off, wipe off the debts, are all the nomenclatures or the terms they use in order to wipe out the industries for a song. The regime is nothing but a way to buy expensive assets at discounted rates as they are purchasing through public money and the public money has no real value in this nation. Thank you very much, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR RAY): Thank you. Now, Shri Vijay Pal Singh Tomar. आपका बोलने का समय पांच मिनट allot किया गया है।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश) **:** धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में, विषम परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हमारे देश की जीडीपी 7.6 है, जबकि चीन की जीडीपी हमसे कम रही है। इसका कारण यह है कि जब प्रधान मंत्री जी 2014 में आए, तब उन्होंने पार्लियामेंट की चौखट पर सिर झुकाकर यह कहा था कि मेरी सरकार गरीब, वंचित, किसान और गांव को समर्पित है। प्रधान मंत्री जी ने जो संकल्प लिया, उसको पूरा करने का काम भी किया।

महोदय, मैंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ काम किया है। वे कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता खेत-खलिहान, गांव और गरीब से होकर गुजरता है। जब भारत विश्व का आर्थिक रूप से सबसे सम्पन्न राष्ट्र था, तब देश के 80 फीसदी लोग खेती से जुड़े हुए थे और 82 फीसदी लोग गांव में रहते थे। आज मैं देश पर 50 साल तक राज करने वालों से पूछना चाहता हूं कि गांव में रहने वालों की संख्या घटकर 62 फीसदी और खेत में काम करने वालों की संख्या 55 फीसदी क्यों रही? ऐसा इसलिए क्योंकि उनको गांव में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सभी सहूलियतें उपलब्ध नहीं हुईं। प्रति व्यक्ति गांव पर एक-तिहाई भी शहर के मुकाबले में खर्च नहीं हुआ। इसीलिए किसान की हालत मजदूर से नीचे चली गई और हालत यह हुई कि किसान खेती छोड़ने लगे।

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी की प्राथमिकता में यह रहा कि हम किसान की, महिलाओं की, गांव की और गरीब की चिंता करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर किसी के पास मकान हो, मकान में शौचालय हो, मकान में गैस का कनेक्शन हो, मकान में बिजली का कनेक्शन हो और उसमें रहने वाले गरीब का बच्चा बीमार है, वह मर न जाए, उसकी बीमारी के इलाज के लिए उसके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड हो। आज माननीय प्रधान मंत्री जी के कारण करीब चार करोड़ घर प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से आए और उनमें से 60.89 परसेंट मकान महिलाओं के नाम पर हैं। इसी तरह से 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस के कनेक्शन्स मिले हैं और साढ़े 11 करोड़ शौचालय बने हैं। मुझे याद है कि चौधरी साहब शाम के समय हर भाषण में कहा करते थे कि जब गाड़ी जाती है तब महिलाएं सड़कों के किनारे खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रोशनी पड़ती थी और वे उससे बचने के लिए खड़ी हो जाती थीं। उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था और उन्होंने इस कार्य को करने का काम किया। करीब 12 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड देने का काम किया गया। मुद्रा बैंक से जिनको ऋण मिला है, उसमें भी 58 परसेंट से अधिक ऋण महिलाओं को दिया गया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस में पहले एक भूतपूर्व प्रधान मंत्री रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम सौ रुपये भेजते हैं, लेकिन नीचे पंद्रह रुपये पहुंचते हैं, 85 रुपये बीच में खाए जाते हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने दो ही काम किए हैं। उन्होंने एक काम तो यह किया है कि बीच की दलाली समाप्त कर दी। आज अगर सौ रुपये भेजेंगे तो सौ के सौ रुपये नीचे जाएंगे। उन्होंने दूसरा काम यह किया है कि जो बात गाँव, गरीब और किसान से संबंधित थी, उसके लिए वरीयता रखी। इसीलिए जब रोज़गार की बात आती है, तो रोज़गार का मतलब सरकारी नौकरी से नहीं है, रोज़गार का मतलब अन्य क्षेत्रों से भी है। आपने देखा होगा कि माननीय मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या किया है।

[**उपसभाध्यक्ष (डा. सोनल मानसिंह**) *पीठासीन हुईं*]

50-60 सालों तक राज करने वाले बताएं कि देश भर में 2014 से पहले केवल 723 विश्वविद्यालय थे, परंतु आज कितने विश्वविद्यालय हैं? आज 1,113 विश्वविद्यालय हैं। पहले देश भर में 5,298 डिग्री कॉलेजेज़ थे, आज कितने डिग्री कॉलेजेज़ हैं? ये डिग्री कॉलेजेज़ नौ सालों में बढ़कर अब 43,796 हो गए हैं। पहले केवल 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स थे, लेकिन आज इनकी संख्या 23 है। ये मेडिकल इंस्टीट्यूट्स नौ वर्षों में 15 बढ़े हैं, जबकि 50-60 वर्षों में केवल आठ बने थे। इसके साथ ही 7 नए आईआईटीज़, 7 नए आईआईएम्ज़, 225 नये मेडिकल कॉलेजेज़ और 442 स्टार्ट अप्स थे, जो आज बढ़कर 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो भूतल परिवहन मंत्रालय है, आपके टाइम में उसका कितना बजट था? अगर यू.पी.ए. के लास्ट ईयर का देखते हैं, तो यह लगभग 34 हज़ार करोड़ रुपये है। भूतल परिवहन मंत्रालय का इसी साल का बजट 2 लाख, 70 हज़ार, 435 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में रोड्स भी बन रही हैं। पहले आपके समय में 12 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बनती थी, लेकिन अब 35 किलोमीटर का हाइएस्ट रिकॉर्ड रहा है, वैसे एवरेज़ भी 29 किलोमीटर पर डे की है। यह दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। क्या यह काम नहीं हो रहा है? इतना पैसा है, तो इसमें रोज़गार भी होता ही है। महोदय, इसी तरह से मेट्रो ट्रेन की बात है। 2014 तक यह पाँच शहरों में 229 किलोमीटर तक पहुँची थी, आज 20 शहरों में 860 किलोमीटर तक पहुँच गई है। 2014 तक रेलवे लाइन का विद्युतीकरण 21,413 किलोमीटर तक हुआ था, लेकिन इन नौ वर्षों में यह 58,424 किलोमीटर तक हो गया है। किसानों के बजट में भी 6 गुना वृद्धि की गई है।

महोदय, आपका 2009-10 का बजट देखा है। यह बजट यूपीए के टाइम में किसानों के लिए 12 हज़ार करोड़ रुपये था। अगर पाँच सालों का हिसाब लगाएं, तो 1 लाख, 23 हज़ार करोड़ रुपये का बजट था। हमारा पिछले साल का 1 लाख, 25 हज़ार करोड़ रुपये का बजट था, इसीलिए हम किसानों को सब्सिडी देने का काम कर पा रहे हैं। हमने एक वर्ष में 2 लाख, 54 हज़ार करोड़ की सब्सिडी दी है।

महोदय, मैं भी किसान गाँव से ही आता हूं, कल माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि डीएपी के एक बैग की इंटरनेशनल मार्केट में 4,070 कीमत है, लेकिन यह हमारे यहाँ के किसान को कितने रुपये में मिल रहा है? यह हमारे यहाँ के किसान को 1,370 रुपये में मिल रहा है। एक यूरिया के बैग की कीमत 2,450 है, लेकिन यह हमारे किसान को 266 रुपये में मिल रहा है। यह पैसा कौन दे रहा है? यह पैसा मोदी जी की सरकार दे रही है। एनपीके, एमओपी, जो 3,200 व 2700 रुपये के हैं, वे 1300, 1,700 रुपये में मिल रहे हैं। इस तरह से किसान को सब्सिडी देकर, एमएसपी को डेढ़ गुना करने का काम किया गया है ताकि उसकी लागत नहीं बढ़े।

महोदय, 2006 में स्वामीनाथन रिपोर्ट आ गई थी, फिर भी आपने उसको लागू क्यों नहीं किया? हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की। हमने इस साल भी लागत के डेढ़ गुना मूल्य बढ़ाया है। इस बार भी धान का मूल्य 150 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग का 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा है। सरकार ने एमएसपी बढ़ाने का काम किया है, MSP पर अधिक खरीदारी करने का काम किया है। मैं इसके साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि

इंटरनेशनल मार्किट में हमारे किसानों की जो डी ए पी प्रति बैग पर बचत हुई है, वह 2,700 रुपये प्रति बैग की हुई है। यूरिया पर करीब 2,450 रुपये प्रति बैग की बचत हुई है।

महोदय, मैं इसके साथ ही एक और बात कहना चाहता हूं। रक्षा के क्षेत्र के बारे में अभी माननीय दिनेश जी ने बताया है कि हम 16 हज़ार करोड़ रुपये के यंत्र निर्यात कर रहे हैं, जबकि हम पहले आयात किया करते थे। महोदय, ऐसे 4,100 आइटम्स हैं, जिनका आयात बंद हो गया है। वे स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए यहीं पर निर्मित होने लगे हैं। हमारे यहाँ पर 50 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोले गए हैं, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया गया है।

महोदय, कोरोना महामारी में दुनिया देख रही थी कि लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री से यूएनओ में कहा गया था कि यूरोप में तो संपन्न देश हैं, भारत का क्या होगा? मोदी जी ने अपने यहाँ के डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों, फार्मा कंपनियों को बुलाया और कहा कि हमारे यहाँ सबसे पहले वैक्सीन आनी चाहिए। हमारे देश में सबसे पहले तीन वैक्सीन्स आईं, देश में 222 डोज़ लगाई गईं और उन्हें 110 देशों में भी भेजने का काम किया गया। आज हम दुनिया को देने वाले हैं, आज हम लेने वाले नहीं हैं। भारत बदला है। यह मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ भारत है। आज हर घर नल से जल पहुँचाने की बात आई।

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Please conclude.

श्री विजय पाल सिंह तोमर : एक मिनट, मैडम। माननीय प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं गाँव में जाता हूँ। मैं भी गाँव में जाता हूँ। मुझे तो कोई घर वैसा नहीं मिलता। मैंने कहा कि अब तो जाड़े का सीजन आ गया, मक्के की रोटी बनाओ और साग बनाओ। वैसा चूल्हा किसी के यहाँ नहीं है। आज हर घर में गैस है और उससे रसोई चल रही है। पाइपलाइन हर गाँव में बिछी हुई है। पाइप लग गई है और अब उसमें से पानी जा रहा है। करीब 8.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुँच चुका है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस के कनेक्शंस दिए गए हैं। कल भी एक बात आई थी कि किस तरह से गरीब महिलाओं की मदद करने का काम किया गया। 27 करोड़ को सैनिटरी पैड एक रुपए प्रति पैड से दिए हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सोनल मानसिंह) : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री विजय पाल सिंह तोमर : जी, मैडम। हमारे करीब 10,000 जन औषधि केन्द्र हैं, अब 2024 तक और खुलने जा रहे हैं। गरीब को सस्ती दवा उपलब्ध हो, कोई गरीब का बच्चा मर नहीं जाए, इसकी चिन्ता करने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया है। ...(**समय की घंटी**)... मैं सरकार को और अपने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। विषम परिस्थितियों में देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधान मंत्री जी ने 2027 तक देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया है, उसे वे निश्चित रूप से सिद्धि तक पहुँचाने का काम करेंगे और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सोनल मानसिंह) : धन्यवाद। माननीय श्री राघव चड्ढा जी।

श्री राघव चड्ढा (पंजाब) : महोदया, अच्छे दिन का वादा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आयी।

उपसभाध्यक्ष (डा. सोनल मानसिंह) : अच्छे दिन तो आ गये।

श्री राघव चड्ढा : 2014 के बाद आज तक शायद ही इन्होंने इस अच्छे दिन के जुमले का प्रयोग किया होगा। 2019 के चुनाव से पहले एक वादा जरूर किया, देश की जनता को एक और ख्वाब दिखाया कि हम एक 'न्यू इंडिया' बनाएँगे और 2022 में जब भारत देश की आज़ादी के 75 साल हो जाएँगे तो 'अमृतकाल' आएगा, 'न्यू इंडिया' आएगा और हम ये बड़ी चीजें करेंगे। अब 2024 का चुनाव आ गया। कम से कम 2024 के चुनाव से पहले जो 'न्यू इंडिया' का वादा था और इन्होंने जो 25 बड़े वादे किये थे कि हम 2022 तक ये हासिल कर लेंगे, उनका आकलन होना चाहिए। आज मैं वादा बनाम वास्तविकता की, वादा बनाम सच्चाई की पूरी सूची लेकर आया हूँ और उसे आपके सामने रखना चाहूँगा।

महोदया, पहला वादा यह था कि 2022 तक भारत देश 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। आज सच्चाई यह है कि हम उस वादे से बहुत कोसों दूर हैं। सवाल यह नहीं है कि पाँच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत बनेगा या नहीं बनेगा। अगर सरकार अपनी ऊँगली भी नहीं उठाए, तब भी हम बन जाएँगे, लेकिन सवाल यह है कि हम बनेंगे कब - 2037 में, 2028 में या 2030 में? लेकिन यह वादा पूरा नहीं हुआ।

दूसरा वादा यह किया कि 2022 तक हर भारतीय के पास एक बैंक अकाउंट, life insurance, accident insurance, pension और retirement planning सेवाएँ होंगी। सरकार की अपनी ही रिपोर्ट यह बताती है, 2022 की Economic Survey की रिपोर्ट सच्चाई दिखलाती है कि हर 100 लोगों में मात्र 3 लोग ऐसे हैं, जिनके पास life insurance है और हर 100 लोगों में मात्र एक आदमी या एक औरत ऐसी है, जिसके पास life insurance छोड़ कर अतिरिक्त insurance है। यह सच्चाई है। 'जन-धन योजना' में अकाउंट्स तो खुलवा दिए, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कभी मुड़ कर उन अकाउंट्स की ओर भी देखा कि कितने खाते खाली हैं, कितने अकाउंट्स dormant हो गए?

इन लोगों ने जो तीसरा वादा किया था, वह यह था कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। मैडम, अब ये इस वादे की बात भी नहीं करते। आय तो छोड़िए, सरकार ने पिछले 5 सालों में किसान का कर्जा दोगुना करने का काम किया। पिछले 18 quarters की सबसे lowest growth agricultural sector में इस quarter में देखी जा रही है, जो कि चौंका देने वाले आंकड़े हैं।

चौथा वादा जो किया था, वह यह था कि 2022 तक हर भारतीय के पास अपना घर होगा। सच्चाई आप जानती हैं कि कितने भारतीयों के पास अपना घर है। आम आदमी का घर तो छोड़िए, यहाँ पर सांसदों तक का घर छीना जा रहा है, यह सच्चाई है।

पाँचवाँ वादा यह किया था कि हर भारतीय के पास 2022 तक शौचालय होगा, यानी access to toilet होगा। अगर यह वादा पूरा हो गया होता, तो भारत में open defecation नहीं बढ़ता और National Family Health Survey की रिपोर्ट यह नहीं बताती कि आज लगभग 20 प्रतिशत Indian households ऐसे हैं, जो बिना toilet facility के जी रहे हैं और जहाँ-जहाँ नाम के वास्ते एक कमरे का टॉयलेट बना भी दिया, वहाँ पानी की सप्लाई नहीं पहुँची, सिर्फ इमारत खड़ी हो गयी। छठा वादा यह किया कि 2022 तक हर भारतीय के पास 24 घंटे, सातों दिन बिजली होगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को छोड़कर, भारत देश के किसी एक सूबे में भी 24x7 इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो मैं चुनौती देता हूँ कि सरकार के मंत्री मुझे आज यह बताएं। महोदया, 24x7 इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के गाँव में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नोएडा ही चले जाइए और बताइए कि क्या 2022 तक इन लोगों ने नोएडा में भी 24x7 इलेक्ट्रिसिटी देने का काम पूरा किया है! आज भी घंटों-घंटों के पावरकट लग रहे हैं। 7वां वादा - Every household will have LPG cylinder. 2022 तक हर घर के पास एलपीजी सिलेंडर होगा। वास्तविकता यह है कि एलपीजी के प्राइस बढ़ गए, सब्सिडी बंद हो गई और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी थे, आज एक बार सिलेंडर रीफिल कराने में भी उन्हें नानी याद आ जाती है। जेब पर इतनी * डाली जा रही है। 8वां वादा था - Every Indian in rural areas will have a water connection by 2022.

उपसभाध्यक्ष (डा. सोनल मानसिंह) : माननीय सदस्य, * शब्द सुबह... प्लीज़, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

श्री राघव चड्ढा : मैं उसे withdraw करता हूँ। * शब्द को withdraw करता हूँ।

8वां वादा था कि हर भारतीय के पास, जो ग्रामीण इलाकों में रहता है, 2022 तक अपना पानी का कनेक्शन होगा। सरकार के खुद के मंत्री ने अप्रैल, 2023 में राज्य सभा के पटल पर जवाब देते हुए बताया कि 40 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण परिवारों, रूरल हाउसहोल्ड्स के पास आज भी टैप वाटर सप्लाई नहीं आती है, नलके में पानी नहीं आता है। न तो नलका है, न पानी है! मैं आगे चलता हूँ।

सरकार ने 9वां वादा किया था कि 2022 तक भारत देश मालन्यूट्रीशियन मुक्त हो जाएगा, यानी 2022 तक भारत देश से कुपोषण खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। * सच्चाई यह है कि आज चाइल्ड मालन्यूट्रीशियन में भारत देश दुनिया के मुकाबले सबसे खराब स्थिति में खड़ा हुआ है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि 121 देशों में भारत की रैंकिंग 107-108 पर है। यह स्थिति है कि भारत देश की 74 प्रतिशत आबादी हैल्दी फूड अफॉर्ड नहीं कर सकती है, यानी लगभग सौ करोड़ के पास इनसफिशिएंट न्यूट्रीशियन पहुँच रहा है। यह सच्चाई है। 10वां वादा किया कि 2022 आते-आते हर ग्राम पंचायत के पास अपना फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होगा। सच्चाई यह

---

* Withdrawn by the hon. Member.

है कि आज तक रूरल एरियाज़ में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की जो स्थिति है, उसका एक जायज़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले ले, तो पता लग जाएगा। हमारे देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी गाँवों में बसती है, लेकिन वहाँ अभी तक ग्राम पंचायतों के पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट नहीं पहुंचा है। 11वां वादा किया था कि 2022 तक सौ प्रतिशत डिजिटल लिटरेसी आ जाएगी। आपको एनएसएसओ का डेटा बताएगा कि अभी आप अपना आधा लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाए हैं। 12वां बड़ा दिलचस्प वादा - है कि 2022 तक हिन्दुस्तान की सड़कों पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। अब तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि भाजपा का नारा है - बुलेट ट्रेन में बिठाएंगे, देश की सैर कराएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ...(**व्यवधान**)... अब मैं आगे चलता हूँ।

भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से जो 13th प्रॉमिस किया था, वह यह था कि हम 2022 तक रेल दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या को शून्य कर देंगे, यानी एक भी मौत नहीं होगी। इसी साल हमने बालासोर, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में वह त्रासदियाँ देखी हैं, जिन्होंने हमारी आँखें खोलकर रख दीं, हमारी आत्मा को झकझोर दिया, ऐसे हालात रेल दुर्घटना से हमारे सामने आए।

14वां वादा किया था कि Growth rate in manufacturing sector will double by 2022. हम इसे लगभग 14 प्रतिशत के आस-पास लाकर खड़ा करेंगे। 14 प्रतिशत तो छोड़िए, पिछले दो वित्तीय वर्षों से हम पाँच या छः प्रतिशत पर मंडरा रहे हैं। आरबीआई का अपना खुद का टारगेट साढ़े छः परसेंट पर है। 15वां वादा था कि 20 मेडिकल फ्री जोंस बनाएंगे, to attract medical tourism. यह सिर्फ वादा था, कोई डिलीवरी नहीं हुई। 16वां वादा किया कि अंडर डेवलप्ड इलाकों में 100 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनेंगे। यह सिर्फ वादा था, इस पर भी कोई काम नहीं किया गया। 17वां वादा था कि दस नए इनोवेशन डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, जहाँ पर entrepreneurs और डिजाइनर्स लिव, वर्क एंड प्ले की नीति के तहत काम कर पाएंगे। यह सिर्फ वादा था, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। 18वां वादा था कि हम 2022 तक मैनुअल स्कैवेंजिंग को शून्य पर लाकर खड़ा कर देंगे। Manual scavenging will be eradicated. सच्चाई यह है कि मंत्री जी खुद अपने जवाब में सदन में बताते हैं कि पिछले पाँच सालों में 339 डैथ्स सेप्टिक टैंक्स में हुईं और वर्ष 2022 में अकेले मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से 66 रिपोर्टेड डैथ्स हुईं। इसके अलावा न जाने कितनी ही अनरिपोर्टेड डैथ्स हैं, जिनका आंकड़ा ही नहीं है। 19वां वादा था कि हम proportion of formally-skilled labour to workforce को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर देंगे। सच्चाई यह है कि 2023 खत्म होने को आ रहा है, formally-skilled labour 15 परसेंट तो छोड़िए, बल्कि हम आज पाँच परसेंट पर मंडरा रहे हैं। जहाँ यूके में यह आंकड़ा 68 परसेंट है, जर्मनी में 75 परसेंट है, यूएस में 52 परसेंट है, जापान में 80 परसेंट है, वहीं भारत देश पाँच प्रतिशत के आस-पास खड़ा हुआ है। 20वाँ वादा यह किया था कि नई नौकरियां देंगे - 3 million jobs in healthcare; 40 million jobs in tourism; and, 5 million jobs in mines and minerals. नौकरी की तो जितनी बात की जाए उतनी कम है, मिलने की बजाय नौकरियां जा रही हैं। 21वाँ वादा - 2022 तक सिंगल प्लास्टिक यूज़ बैन हो जाएगा। नोटिफिकेशन लाकर बैन तो कर दिया, लागू कितना हुआ, यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। 14 मिलियन टन प्लास्टिक इस साल भी हिंदुस्तान में यूज़ किया गया। बस, अब मैं समाप्त कर रहा हूं। 22वाँ वादा - क्रूड ऑयल और गैस के जो इम्पोर्ट्स हैं, 2022 आते-आते वे 10 प्रतिशत घटा दिए जाएंगे। 10 प्रतिशत तो छोड़िए, उसके चलते क्रूड ऑयल का हमारा जो

इम्पोर्ट बिल है, वह डबल हो गया। गैस, क्रूड, इन सबका इम्पोर्ट भारत देश में बढ़ता जा रहा है। 23वाँ वादा यह था कि हम नेशनल हाईवे की लेंग्थ को बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर कर देंगे। सच्चाई यह है कि 2 लाख किलोमीटर तो छोड़िए, 30 नवंबर, 2022 को गवर्नमेंट का अपना आंकड़ा बताता है कि हम लगभग 1,44,000 किलोमीटर के आसपास खड़े हैं, यानी इस वादे में भी फेल हो गए। 24वां वादा - यह बड़ा दिलचस्प है, आप सुनिएगा - No crop residue burning to reduce air pollution and PM-2.5 levels will come down to 50 by 2022. यानी पीएम 2.5 का लेवल 50 से नीचे आ जाएगा।... (**समय की घंटी**)... सच्चाई यह है कि आज भी पूरा उत्तर भारत गैस चैंबर बना हुआ है। केवल दिल्ली-चंडीगढ़ ही नहीं ,बल्कि लखनऊ-वाराणसी में भी वायु प्रदूषण है। सरकार को इसका समाधान ढूंढना चाहिए।न्होंने 25वाँ और आखिरी वादा यह किया था कि we would achieve a doctor-population ratio of, at least, 1:1400, and a nurse-population ratio of, at least, 1:1500. यह वादा पूरा करने में भी यह फेल रही।

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Please conclude.

श्री राघव चड्ढा : सच्चाई यह है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हों या CHCs हों, इन सब में डॉक्टर्स और नर्सेज़ की शॉर्टेज है। उसे बढ़ाना तो दूर, जो एक्जिस्टिंग सेंटर्स हैं, आज उनमें भी फोर्स नहीं है।

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Please conclude.

श्री राघव चड्ढा : मैं अंत में बस इतना कहूंगा कि 25 वादे सरकार ने किए थे कि ये बड़े वादे हम 2022 तक पूरे करेंगे। इन 25 में से एक वादा भी पूरा नहीं किया, अब क्या मुंह दिखाकर ये 2024 में लोगों से वोट मांगने जाएंगे? ...(**समय की घंटी**)... कोई साधारण आदमी अगर वादा कर वादाखिलाफी करता है, तो उस पर कार्रवाई होती है, उस पर पर्चा दर्ज हो जाता है, 420 की धाराएं लग जाती हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सोनल मानसिंह) : माननीय सांसद जी, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राघव चड्ढा : जब सरकार वादा करके मुकरती है, तो जनता की अदालत उसका फैसला करेगी। मैडम, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत!

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Madam, first of all, I would like to congratulate the Government and the hon. Finance Minister -- she is not here -- for the kind of direction that has come to the economy which was reflected in the last quarterly result of GDP, which grew at the rate of 7.6 per cent in the July-September quarter of the Financial Year 2023-24 beating all expectations by all the rating agencies. I am also happy by the fact that under the leadership of our hon. Chief Minister, Shri Naveen

Patnaik, our State also has been beating the national growth rate consistently for the last ten years. The trajectory of growth, that has been set in motion by the Government during the last five or six Budgets with particular emphasis on capital expenditure, I think, is in the right direction. The policy push has been reflected in the consistent economic growth.

Now, I would like to draw your attention to a few of the global economies and how they have fared during this period because that would set the context for seeing how Indian economy has performed during this period. If we see 2022 GDP growth figures, India growth rate stood at 7.2 per cent. I am quoting the IMF figures. China was at 3 per cent; U.K. at 4.1 per cent; the U.S. at 2.1 per cent; and, Germany at 1.8 per cent. The IMF's projected GDP growth rate for India during 2023 is 6.3 per cent. If we go by what has happened today, I think, we are going in the right direction and would, probably, be beating that projection.

Now, I have heard from the Opposition benches here as many of my colleagues have talked about a number of things that India should have been doing and India should have been achieving, but for all that, we need the GDP to grow and that is what is happening. So, I think, the thrust of this current debate that we are having in this Short Duration Discussion is: Where are we heading as far as the Indian economy is concerned? I think, we are on a strong wicket. Having said so, I would also like to state that it is important to look into granular details of what has spurred this growth and what has to be done further. What I am going to say now is that we are in a very nice position to bring in structural changes in the economy. We are going in that direction. Over reliance on private consumption expenditure to shift towards an investment-oriented growth strategy, I think, is a step in the right direction but for that, the policy push has to be stable and consistent.

Let me look at the real gross value added because that indicates the actual value addition that has taken place in the economy and these are the latest figures. Here, there are some concerns, and, therefore, my suggestion to the Treasury Benches is to somehow ensure that these fault lines are addressed. Firstly, on the Agriculture, Forestry and Fishing, if we look at the figures from 2019 onwards, it has consistently decreased. In the Agriculture, Forestry and Fishing, it has consistently declined and it has come to 1.22 per cent in 2023. It is a cause of worry because food security, whatever said and done, is one of the most important requirements for the growing population and growing economy. Agriculture and Allied sector has seen this steady decline from 4.3 per cent it grew during the pandemic years, which made us survive the pandemic, to 1.2 per cent. What it calls for is investment in agriculture, and, therefore, the Government came up with Agriculture Infrastructure Fund.

However, against the projected one lakh crore spending in the agriculture sector in this particular scheme, only 26,000 crore of rupees have been sanctioned and only 21,000 crore of rupees have been spent. I think, a lot requires to be done in the rural sector.

Coming to the Swaminathan Committee Report, which has been talked about for increasing the income of the farmers and for fixing the Minimum Support Price, it is yet to be done. It has to be based on the C2 formula, that is, the composite price, and, it has been the consistent demand of our Party, the Biju Janata Dal under the leadership of our Chief Minister, Shri Naveen Patnaik. We have been raising this demand at all fora. That is not happening but that has to happen. The deceleration in the agriculture translates into some stress in the rural sector and this has to be recognized. The rural economy has to go up in case we have to maintain the growth momentum and the structural shift remains where it is and it does not change its position frequently year on year.

If we see the services sector, the growth rate in the services sector has come down to 5.8 per cent and this is a deceleration. Previously, our economy was heavily dependent on the services sector but what happens if the services sector goes down. Particularly in the trade, hotels, transport, communication or broadcasting services, it has just grown by 4 per cent. These are the sectors which provide jobs. Unless we grow in these sectors by consistent policy efforts by budgetary allocation, by increasing private investment in these sectors, jobs will not be created and the unemployment problem will consistently haunt us and, therefore, this is something which the Government has to think about.

Madam, I also want to talk about the social sector. In the social sector, the last Economic Survey mentioned that out-of-pocket expenses are 48 per cent. This has to decrease, and, therefore, Government's spending on health has to increase but this has not happened. It has to be consistently done given the fact that our economy is growing at a healthy rate. The growth of the Indian economy depends on the growth of the State economies and the growth of the State economies can increase only when the Central allocation, by way of devolution of funds, increases. What we have seen is that it has consistently decreased and currently, it is at 30 per cent, which is not doing good to the economic situation in the States. We have to ensure that the regional imbalance that exists between several States in terms of attracting foreign investment because of the infrastructure which is already there, has to be addressed by either declaring some of the States like Odisha or Andhra Pradesh as special focus States or by making infrastructure push in these sectors which will lift them to a level where foreign direct investment can also come into these sectors.

Madam, there is a point that I wanted to make relating to tax-to-GDP ratio. Tax-to-GDP ratio has shown a good trend recently. The GST collection has increased, which basically means that formalization of economy is taking place. But, at the same time, 90 per cent of the people are still employed in informal economy. This is a contradiction which, I think, the Government needs to address at some point of time because unless this is addressed, a structural problem may still remain in the economy even as we are growing in GDP terms. The tax-to-GDP ratio at 11.1 per cent is at par with 2023 Revised Estimates, but it is less than the average of many emerging economies, including the OECD economies where it is 33 per cent. So, we have to bring this structural change in our economy in terms of revenue collection tax as a percentage of GDP.

The last point, Madam, which I want to make is relating to private sector investment. The investment that has already happened which is spurring this economic growth, which our economy analysts are also saying is basically backed by the Government capital expenditure, which is welcome. *(Time-bell rings.)* But this capital expenditure has to be backed by the investment from the private sector in the economy. The households sector's investment in the economy is already happening, but the private sector's investment is not happening. This is a cause for worry, and for that, I think, several more policy push have to be made because this would be another source in which jobs can be created, employment opportunities can be created and unemployment can be addressed.

Lastly, Madam, there was a talk about female labour force participation. There was a discussion as to the stark reality of our female labour force participation being very low compared to other countries.

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Please conclude.

DR. AMAR PATNAIK: Actually, there is an increase in female labour force participation, thanks to the Government, by 37 per cent in 2023. Several such measures will have to be taken to bring it to a level in which we can be comparable to other countries. So, in short, Madam, I would like to say that the economy is in good hands, but there are fault lines. *(Time-bell rings.)* These fault lines have to be addressed. And if that happens, then the country's growth trajectory will be more inclusive, more sustainable and it will benefit all sections of the society. Thank you.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA (Andhra Pradesh): At the outset, I would like to thank the hon. Vice-Chairman Madam for giving me the opportunity to speak on the

economic situation prevailing in the country. I would like to emphatically state that the 20th century belonged to China but the 21st century belongs to India. India has emerged as one of the fastest growing economies in the world despite challenges in the global environment. Those challenges include the rise in geopolitical tensions, disruption of supply chains, global tightening of monetary policies and inflationary pressures. The economy is projected to grow at 6.5 to 7 per cent rate in the fiscal year 2024, but the country's economy expanded 7.6 per cent in July-September quarter, surpassing the projections of 6.5 per cent of growth estimates by the RBI. India's growth rate is almost twice the average of emerging market economies. What is really working for us? India's economic progression is being powered by the Government's emphasis on public infrastructure investment, capital expenditure and increased bank rate growth. Government spending has been up by 12.4 per cent. Manufacturing and construction sectors have also seen growth with the rise in demand for new projects. The biggest boost in the growth came from the services sector which grew at 10.3 per cent in the first quarter, up from 6.9 per cent in the previous quarter. This can be attributed to strong growth in the financial, agriculture, real estate and other services sectors as well. As an emerging economy, India has been able to control its inflation while many advanced economies are dealing with severe inflation and have not yet been able to stabilize their economies. According to IMF estimates, the Indian economy will emerge as the world's third largest economy by 2027, surpassing Japan's and Germany's GDP, as we are going to cross five trillion dollars. Madam, India's digital infrastructure is the best in the world. Our digital infrastructure development has helped in faster delivery of financial services and helped make a positive impact on financial inclusion. According to the G-20 Policy Document prepared by the World Bank, India has achieved a remarkable 80 per cent financial inclusion rate in just six years -- a feat that would have taken nearly five decades without a digital public infrastructure approach. Andhra Pradesh Government, under the able and dynamic leadership of Mr. Jagan Mohan Reddy, has used this digital infrastructure to transform the State to the next level.

Madam, I would like to mention the developmental statistics that Andhra Pradesh has given in the economic situation of our country. Andhra Pradesh records 50 per cent GSDP growth in four years -- jumping from 16 to 4. In March 2019, Andhra Pradesh ranked, in terms of growth rate, 16th out of 28 States with GSDP of 8.7 lakh crore rupees. However, as per the latest RBI Report, 2022-23, Andhra Pradesh jumped to rank four in terms of the GSDP growth in the country with a GSDP of 13.17 lakh crore rupees. The State recorded 50 per cent GSDP growth in the last four years.

There has been a significant uptick in per capita income. Andhra Pradesh moves from spot 17 to 9. In March 2019, Andhra Pradesh ranked 17th in the country with a per capita income of 1.5 lakh rupees. In just four and a half years of CM Jagan-led Government, the per capita income has increased to 2.1 lakh rupees and currently has acquired ninth spot among other States. These are all from the RBI's Handbook of Statistics.

The debt growth rate is down by 111 per cent -- from 169 per cent in 2014 to 58 per cent in 2023. Under the Chandrababu Naidu's Government, in 2014, the debt growth rate of State was as high as 169 per cent.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: Madam, he is taking the name. ...(*Interruptions*)...

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Hon. Member, name should not be mentioned. ...(*Interruptions*)...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: However, after gaining power, Mr. Jagan Mohan Reddy not only took measures to elevate the State's economic growth but also ensured that the debt growth slid down. ...(*Interruptions*)...

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Hon. Member, name should not be mentioned. ...(*Interruptions*)...

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Madam, after four and a half years, the debt growth rate has drastically come down from 110 per cent to 58 per cent. This is also as per the records available.

There is a record generation of government jobs. During 2014-2019, only 34,000 posts in government jobs could be filled. But in the last four and a half years of YSRCP Government, 4.93 lakh government jobs have been created. ...(*Interruptions*)...

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Hon. Member, please refrain from mentioning names.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Madam, ascending agricultural growth has contributed to the nation's economy. ...(*Interruptions*)... My friend, you have to understand this. There is ascending agricultural growth from second last to number

seven in India. In March 2019, in terms of agricultural sector growth, Andhra Pradesh was ranked 27th in the country with a negative growth rate of 6.5 per cent. However, in a significant change, the State has ascended to 7th position in the last four and a half years. Andhra Pradesh's agricultural growth rate now has been recorded as +5.5 per cent. This is again from Handbook of Statistics of the RBI.

We have three times growth in industrial sector performance. During 2019, industrial growth rate was a meagre 3.2 per cent. But, today, under Chief Minister Jagan's Government, the industrial growth rate has increased to 10.59 per cent. Again, this is from RBI statistics. Andhra Pradesh tops consecutively for two years in 'ease of doing business'. This again is a source from the Ministry of Commerce and Industry, Government of India. There is record five times growth in MSMEs in the last four years. During 2019, when my CM took over, there were only 37,956 MSMEs. But, in the last four-and-a-half years, it has gone up to 1.88 lakh MSMEs. This statistic is also available on record. Industrialist stalwarts always look up to Andhra Pradesh. ...(*Interruptions*)... Madam, I would like to say that Andhra Pradesh received the highest ever investment of Rs.13.5 lakh crore during a single global investor summit held in March, 2023. ...(*Interruptions*)... All the top industrialists have invested to a huge extent and committed...(*Interruptions*)... These are all as per the statistics available. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Please.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Madam, I think my colleague has to understand. ...(*Interruptions*)... Finally, Madam, there is a revolution in school infrastructure. In the last four years, an amount of Rs.7,112 crore has been spent on Government schools. ...(*Interruptions*)... Introduction of English medium is one of the best governance inputs that has come from the Andhra Pradesh Government. ...(*Interruptions*)... There is 46 per cent exponential rise in healthcare infrastructure. It has increased from Rs.28,000 crore to Rs.41,000 crore. The CM Jagan Government has developed more than 10,000 YSR village health clinics which were never looked at. There is Arogyasri Programme, also free medical camps and what not. There is a massive infrastructure boost -- more than four ports, ten fishing harbours, two airports, 17 medical colleges, three industrial corridors with five nodes, 10,778 Raythu Bharosa Kendras, 15,000 Gram Sachivalayas, 10,000 YSR health clinics have been developed; all over, 31 lakh house *pattas* have been given to poor and another 22 lakh houses are under construction. ...(*Interruptions*)...

Madam, I have a few suggestions for the Government of India. To evolve into a five-trillion dollar economy, India must focus on several key areas, especially new and emerging fields. ...(*Interruptions*)... Digital infrastructure and technology certainly need to be focussed upon; renewable energy needs to be focussed upon; financial sector reforms need to be focussed upon; international trade and relations should be focussed upon. (*Time-bell rings.*) Research and development initiative should be focussed upon; judicial sector reforms should be focussed upon; bureaucratic reforms should be focussed upon. Madam, I must tell you one thing. Under Prime Minister Modi's governance, this country has seen a lot of safety and security. There is a lot of discipline that has come in the system. I must tell you that. Starting from shareholders to the investors, to the industries, banking system, and all the people that are there in the system understand the importance of governance and everybody is following a disciplined route.

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Sir, please conclude.

SHRI AYODHYA RAMI REDDY ALLA: Madam, I would like to congratulate the hon. Prime Minister and the Finance Minister for steering our country during huge global uncertainties in an effective manner while bringing the maximum benefits to the Indian economy through all the diplomatic outreach initiatives. Thank you very much, Madam.

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी (महाराष्ट्र) : मैं माननीय चेयरमैन साहब को शुक्रिया कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करने का मौका दिया। यह विपक्ष की मांग रही है कि अर्थव्यवस्था पर चर्चा हो, तो उन्होंने इसकी परमिशन दी है, इसलिए मैं उनकी आभारी हूं। मैडम, लास्ट फ्यू स्पीकर्स होने का यह फायदा होता है कि हमने सबके फैक्ट्स सुने हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की तरफ से फैक्ट फ्री डिफेंस भी सुना है। ...(**व्यवधान**)... माइक को क्या हो गया है? क्या आवाज कम है? Madam, can you hear me?

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Excuse me for a second. Dr. John Brittas, I am sorry. After her, please. Thank you.

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Madam, add 30 seconds to this disruption. *...(Interruptions)...* So, what I want to say here is, मुझे सबकी बातें सुनने का समय मिला। मुझे खासकर कुछ सांसदों की बातें सुनने का समय मिला, जो कह रहे थे कि मनरेगा की डिमांड आधी हो चुकी है, unemployment के आंकड़े आधे हो चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अगर

उनके आंकड़े सही हैं, तो मनरेगा के बारे में अखबार हमें जो बताते हैं और जो रिपोर्ट्स आती हैं, उनके अनुसार मनरेगा की भारी मांग क्यों हो गई है, यह मांग दोगुनी क्यों हो गई है?

महोदया, इसके साथ ही साथ रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की भी मांग है। मनरेगा का 60 हज़ार करोड़ रुपये का बजट था। आने वाले बजट के लिए उनकी ऐसी मांग है कि मनरेगा के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये का बजट एलोकेट करना चाहिए। अगर मनरेगा की डिमांड आधी हो गई है, तो फिर यह किस वजह से हो रहा है?

महोदया, दूसरी बात, जो मेरी समझ में नहीं आई, वह यह है कि एक माननीय सांसद कह रहे थे, जिनकी आदत है to defend the indefensible कि unemployment और inflation से जनता को किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए उनको चुनाव में भारी बहुमत मिल रहा है। अगर उन्हें inflation, महंगाई को लेकर कोई दुख नहीं है या unemployment आधी हो गई है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि देश की 80 करोड़ जनता को जो राशन मिल रहा है, वह किस वजह से मिल रहा है? इसका मतलब या तो उनके पास रोज़गार है और अगर रोज़गार है तो 80 करोड़ लोगों को इस राशन की जरूरत क्यों आन पड़ी है?

महोदया, अभी GDP की बात हो रही थी। उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि RBI के inflation के आंकड़े breach नहीं हुए हैं। मैं उन्हें याद दिला दूं कि January 2023 में 6.52 per cent inflation था।, February 2023 में 6.44 per cent था, January 2022 में 6.01 per cent था, February 2022 में 6.07 per cent था, March 2022 में 6.95 per cent था और April में 7.79 per cent था। यह inflation, जिसमें RBI के आंकड़ों को breach किया है, यह 6 per cent का है।

महोदया, GDP की बार-बार बात हो रही है। मैं जीडीपी से ज्यादा per capita income पर ध्यान देना चाहूंगी। एक माननीय सांसद ने कहा कि मैं अगल-बगल के देशों की बात नहीं करना चाहूंगा, बल्कि अमरीका और यूरोपियन यूनियन से अपने देश का कंपेरिज़न करना चाहूंगा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी की उन देशों की पर कैपिटा इनकम के comparison में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पर ध्यान दें। मैडम, ये 2022 के आंकड़े हैं, इसमें यूएसए की पर एनम इनकम 63,41,117 है और चीन की 10,51,610 है। हमारा इंडिया कहाँ पर है? इंडिया 1,98,287 पर है। 2014 से देश के देशवासियों की जो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, वह करीब 35 प्रतिशत बढ़ी है। मैं उनसे यह क्रेडिट नहीं छीनना चाहूंगी, पर जो उनकी महंगाई बढ़ी है, वह 123 प्रतिशत बढ़ी है। यानी जो आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपया कहा जाता था, वह इन्होंने आज पूरा कर दिया है। अगर आप कहेंगे कि मैं दाल, चावल और अन्य सभी का दाम भी बताऊं कि वह दाम कितना बढ़ा है, तो जिन आंकड़ों पर पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, यह उससे ज्यादा ही बढ़ा है। (... **समय की घंटी**..) मैडम, मैं आपके एक-दो मिनट और लूंगी। आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं, मैं पहली बार आपसे कह रही हूं।

मैडम, रुपी डेप्रिशिएशन की बात हुई थी। मुझे याद है कि जब माननीय प्रधान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री हुआ करते थे, तब वे रुपी के गिरने पर कितना अफसोस जताया करते थे। इस बारे में उनके कितने ही भाषण उपलब्ध हैं। वे कहते थे कि पाकिस्तान का रुपी stronger हो रहा है, बाकी देशों की currency strong हो रही है, हमारे देश का ही रुपया क्यों वीक हो रहा है? आज दिल दुखी होता है, जब पता चलता है कि हम लोग हिस्टोरिकल लो पर जा रहे हैं। आज

Indian rupee historical low पर है, against the dollar. ऐसा किसकी नीतियों की वजह से हुआ है? I am sure कि माननीया वित्त मंत्री जी हमें इसके बारे में बताएंगी - यशस्वी प्रधान मंत्री जी..। जब हम यह पढ़ते हैं कि poorest performing currency in Asia ... Madam, one last minute, Thank you so much.,

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Madam, please conclude. *...(Interruptions)...* Please conclude. *...(Interruptions)...*

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI: Madam, please one last minute. मैडम, मैं लास्ट में loan write offs के बारे में कहना चाहूंगी।

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Madam, please conclude. *...(Interruptions)...*

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी : बहुत बार यह बात हुई है कि गरीबों पर ध्यान दिया है, गरीबों का उत्थान किया है, लेकिन 10.6 lakh crore loan write off हुआ है, जिसमें से 50 प्रतिशत जो लोन राइट ऑफ हुआ है, वह उन कैपिटलिस्ट्स का हुआ है, जिनका पूरा-पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है।

THE VICE-CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Please conclude. *...(Interruptions)...*

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी : आज जब गरीबी की बात करते हैं, 'सबका साथ-सबका विकास' की बात करते हैं, तो सही मायने में देश में 'सबका साथ-सबका विकास' लाएं। मैडम, आपने मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया है ,इसके लिए thank you so much.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Madam, I am a strong feminist and I need to get two or three minutes more from you. Madam, see a miracle has happened after the speeches of Shri Rakesh Sinha and others. When I was coming from South Avenue, there are some changes that have happened to the Boat Club. Instead of water, it is full of honey and milk. यह पानी शहद और दूध हो गया। After 2014, this country has drastically changed. You know that as to how it has changed. All the indices have been doled out here and I will not refer it to you, Madam, but I will specifically come to certain concerns of my State. Madam, the other day, I had asked a question to the hon. Finance Minster as to the borrowing limits of the State. I got an answer from the Minister. She said 'that we are strict on borrowing limits because the Fifteenth Finance Commission has given a recommendation and I asked her as to what is the

recommendation. It is like this. "Governments at all tiers may observe strict discipline by resisting any further additions to the stock of off-budget transactions." Fine, Madam. It is perfectly okay. Is not Union Government a Government? Are they not part of the Governments which have been referred to by the Fifteenth Finance Commission? They want all the State Governments to shed the borrowing of the PSUs or SPVs. When it comes to the Central Government, just see the National Highway Authority of India? I asked a question and you know as to what is the loan debt of NHAI, Madam. You would be surprised that it is Rs. 3.4 lakh crore. There are other agencies also. They want to discipline the State Governments. What is the total debt of the Union Government? It is Rs. 157 lakh crore, a humongous figure. They are trying to blame the State Government. I come from Kerala. The Kerala's social indices are at par with the western countries. What is this economy? Economy is for the society, for the people. It is just because you want to stack some cash in your house, is that an economy? No. It is the welfare of the people. The average life-span of a Malayali is 12 years more than that from the State of Shri Rakesh Sinha or other States. What is the meaning of that? We live more than those people who are at the North. I will just come to another topic. ...*(Interruptions)*... I want your protection as it is a very serious matter. Now, the point is that we are being penalized. You know, what is the new slogan? The Prime Minister was harping over co-operative federalism. It is not a co-operative federalism but this is crony federalism. You know why? South India has 18 per cent of population and we contribute 35 per cent to the GDP. We are being penalized for the performance. You mop-up so much of resources through surcharges, Rs. 7 lakh crore in a year and then you bring Centrally-sponsored Scheme which cannot be implemented in a State like Kerala because we have crossed the threshold. You want us to open schools. We have already schools there. ...*(Time-bell rings.)*... Madam, please give me time as you have been liberal to everybody. Now, what is happening? There is a strange phenomenon. Somebody was talking about selfie-corners in higher educational institute. मोदी साहब तो सभी जगह पर हैं। You want to add everywhere. Now, one more thing is this. They are contributing one-fifth for the housing scheme whereas three-fourths is being contributed by the State of Kerala. They want to brand the houses which are built. What about the self-respect of the people? Do you want to have branded houses?

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Please conclude.

DR. JOHN BRITTAS: Madam, I am just winding up. We said that there is no need of branding. We should uphold the self-respect of the people. Instead of that, they want to name everything in the name of Prime Minister. ..*(Time-bell rings.)*... Madam, my only submission to you is that the entire credibility of this Government rests with the fact that, the slogan, you need to have prosperous States instead of fleecing the States. You should allow the State Governments to have the resources. You should make sure that there should be equitable divisive process that is happening whereby resources are given to the States. Thank you very much, Madam.

THE VICE- CHAIRPERSON (DR. SONAL MANSINGH): Now Shri Nagendra Ray.

श्री नगेन्द्र रॉय (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं भारत की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हमें यह ध्यान रहे कि हमारा अतीत था, तो अब हमारा वर्तमान है और वर्तमान है, तो भविष्य भी रहेगा। यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालेंगे, तो पाएंगे कि हमारे देश में कुबेर धन था। हमारे देश का नाम था - रत्नपीठ, स्वर्णपीठ - अगर देखा जाए, तो 2014 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था एकदम लाचार हो गई थी।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्रीमती फूलो देवी नेतम**) *पीठासीन हुईं*]

हमें अपने रत्न भंडार में से सोने को गिरवी रखना पड़ता था। भारत के प्रधान मंत्री, माननीय नरेन्द्र दामोदरदास मोदी ने जब भारत को संभाला, तब से आज तक देखें, तो 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत थी और यह वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में थी। सभी व्यवस्थाओं में भारतीय व्यवस्था को दुनिया में bright spot कहा जा रहा है। पिछले नौ वर्षों से भारत की आर्थिक व्यवस्था में एक उल्लेखनीय नीति है। दुनिया हमारी आर्थिक व्यवस्था की सराहना करती है। महोदया, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमारी जो आर्थिक व्यवस्था बनी है, इसके कुछ-कुछ इलाकों में डेवलपमेंट की कमी है। महोदया, डेवलपमेंट इस आर्थिक व्यवस्था की ग्रोथ है, लेकिन हमारे नॉर्थ बंगाल, बिहार के उत्तर-पूर्वी इलाके, असम, नॉर्थ-ईस्ट इलाके में यह एकदम नैरो है। हम गवर्नमेंट से विनती करते हैं कि जल्द-से-जल्द हमारे यहाँ की आर्थिक व्यवस्था दुरुस्त हो। ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAJEEV SHUKLA (Chhatishgarh): Madam, point of order. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (**श्रीमती फूलो देवी नेतम**) : अभी बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)... अभी बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नगेन्द्र रॉय : मैं गवर्नमेंट से आग्रह करता हूँ कि जल्द-से-जल्द हमारे उत्तर-पूर्व भारत को डेवलप किया जाए। ...(**व्यवधान**)... हम चाहते हैं कि हम यह लक्ष्य पूरा करें कि जो जीडीपी है, वह सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंच जाए। ...(**व्यवधान**)... मैडम, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ...(**व्यवधान**)...

5.00 P.M.

श्री राजीव शुक्ला : मैडम, इन्होंने कहा कि 2014 से पहले हमारी अर्थव्यवस्था लाचार हो गई थी, हमें सोने को गिरवी रखना पड़ता था, फिर मोदी जी ने आकर उसको संभाला। उसके बाद तो नरसिम्हा राव जी भी आए थे, उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने सारी अर्थव्यवस्था संभाली थी। उन्होंने 2005 के बारे में यह सही बताया कि मनमोहन सिंह जी के regime में 7 से ऊपर जीडीपी थी, लेकिन आज भी वह जीडीपी नहीं है। ये फैक्ट्स को सुधारकर वक्तव्य दें, यही मेरा अनुरोध है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती फूलो देवी नेतम) : माननीय श्री विवेक के. तन्खा।

श्री विवेक के. तन्खा (मध्य प्रदेश) **:** मैडम, कृपया मेरा टाइम शुरू से स्टार्ट करें।

मैडम, मैं बहुत देर से सभी मेम्बर्स को सीरियसली सुन रहा था। मैं सुन रहा था कि हर व्यक्ति अपने तरीके से इकोनॉमी के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे थे। लोगों ने एम्प्लॉयमेंट की बात की, जीडीपी की बात की, ग्रोथ की बात की, एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, सबकी बात की, लेकिन मैं आपसे पहली चीज़ यह कहना चाहता हूँ कि मैं जब इकोनॉमी को देखता हूँ, तो उसे अपने शहर से देखता हूँ कि मेरे शहर की व्यवस्था क्या है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मैं वहाँ जबलपुर में रहता था। वहाँ पर करीब छः ordnance factories हैं, जहाँ एक लाख से ऊपर लोग काम करते थे। यह 50-60 साल की व्यवस्था है। I am sure, यहाँ के बहुत सारे सांसद जब जबलपुर गए होंगे, तो उन्होंने ordnance factories देखी होंगी। समस्या यह है कि वे ordnance factories, जहाँ लाख-डेढ़ लाख लोग काम करते थे, आज वहां मुश्किल से 10,000 लोग काम करते हैं, तो मैं यह कैसे मानूँ कि इंडिया की economy is doing well. इकोनॉमी तब अच्छा करती है, जब लोगों को नौकरी मिलती है, इन्फ्लेशन कम रहता है, चीज़ें सस्ती होती हैं, जरूरत की चीज़ें आराम से उपलब्ध हो जाती हैं। मैं figures की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास भी बड़े-बड़े figures हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब ancillaries बन्द पड़ी हैं, तब आप कहते हैं कि इंडिया manufacturing hub है! यह कौन सा manufacturing hub है? यह केवल थोड़ा सा digital hub है। जो एक नया डिजिटल मार्केट क्रिएट हुआ है, जो आईटी का एक मार्केट क्रिएट हुआ है, उसकी कुछ चीजें नोएडा आ गई हैं। इसके अलावा, चीन या बाहर के अन्य देशों में जो manufacturing हुआ करती थी, वह तो यहाँ शिफ्ट नहीं हुई है! जो heavy engineering वगैरह की manufacturing है, वह आज भी यहाँ पर नहीं आई है।

मैडम, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब मैं मोदी जी को सुनता हूँ या मंत्रियों को सुनता हूँ, तो वे education की बात कम करते हैं, employment की बात नहीं करते, growth की बात

hardly करते हैं। वे हमको middle-class के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाते। देश में जो एक inclusiveness होनी चाहिए, उसके बारे में वे चुप रहते हैं। वे skill development के बारे में नहीं बताते। वे जो बताते हैं, वह बहुत थोड़ा है। मेरा यह कहना है कि जब jobs चली गई हैं, तो हमको आजकल क्या शब्द सुनने को मिलते हैं - घमंडिया, अमृतकाल! आप पूरे विपक्ष को घमंडिया बोलते रहिए, लेकिन उससे चीजें तो बदलने वाली नहीं हैं! मेरा यह कहना है कि इस देश में पिछले 9 सालों से केवल जुमला और empty promises दिए गए हैं।

मुझे आज याद आ रहा है कि अपने सनी देओल साहब लोक सभा के मेम्बर हैं। उनकी एक मूवी थी, जिसमें वे कहते हैं- तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली, माई लॉर्ड, पर इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह मैं मोदी जी और बीजेपी से कहना चाहता हूँ कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली, माई लॉर्ड, मगर हमको विकास नहीं मिला। हमें विकास actually नहीं मिला। आपने हमको तारीखें दीं। आपने 2016 दी, 2017 दी, 2018 दी, 2019 दी, 2020 दी, 2022 दी, मगर वह विकास कहाँ है, जिस विकास की आप बात करते हैं?

मैं आगे बताना चाहता हूँ। विकास के छः indices होते हैं, जिनमें से एक है economic growth. What is the economy growth? इकोनॉमिक ग्रोथ वह है, जब हम यह देखें कि real wages, यानी जो non-agricultural occupation होता है, जो फार्मर होता है, उसकी wages में क्या इजाफा हुआ? सितम्बर, 2017 से 2022 में it has declined by 0.9 per cent. ...(**समय की घंटी**)... मैडम, मेरा तो 7-8 मिनट का समय है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती फूलो देवी नेतम) : आपका टाइम चार मिनट का ही था, जो कि पूरा हो गया।

श्री विवेक के. तन्खा : मैडम, मेरा टाइम 7-8 मिनट का था।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती फूलो देवी नेतम) : ठीक है, आप दो मिनट और बोल लीजिए।

SHRI VIVEK K. TANKHA: Between 2017-2021, regular workers have declined from 0.7 per cent to 1.3 per cent. इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ कि पहले कुकिंग गैस 100 रुपये की थी, जो अब 200 रुपये की हो गई। मिल्क, जो कि पहले प्रति लीटर 35 रुपये का था, वह 65 रुपये का हो गया। पल्सेज़ के दाम 75 रुपये थे, जो 180 हो गए, आटा 20 रुपये प्रति किलो था, वह 45 रुपये प्रति किलो हो गया, शुगर 35 रुपये में थी, उसके दाम 55 रुपये हो गए, पेट्रोल 70 रुपये में था, उसके दाम 105 रुपये हो गए।

अब इम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो unemployment rate is 42 per cent, labour force participation rate has fallen to 40 per cent from 47 per cent which is already low. In five years, while, the total working population has gone up by 12 crores, the number of people with jobs have gone down to 80 lakhs. इसी तरह मैं एग्रीकल्चर का failure बताना चाहता हूं। ...(**समय की घंटी**)... मैं शॉर्ट में बोल देता हूं।

उपसभाध्यक्ष (**श्रीमती फूलो देवी नेतम**) : 4 मिनट का समय था। अभी अन्य वक्ता भी हैं।

श्री विवेक के. तन्खा : रुपया constantly decline कर रहा है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती हैं कि रुपया गिरा नहीं, बल्कि डॉलर मज़बूत हुआ है। हमारा कहना है कि 'rupee' today is worst performing Asian currency. मेरा यह कहना है कि wealth inequality है, agricultural growth है, रुपये का decline है, financial scandals हैं - आपकी ग्रोथ कहां हुई? यह ग्रोथ तो कहीं नहीं दिखती। मुझे सिर्फ यह दिखता है कि आप लोग opposition के against full tirade launch करते हैं, opposition को एक bad name देते हैं, कभी कह देते हैं कि अमृतकाल है, कभी कह देते हैं कि यह घमंडिया है। इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ हो, जो मैं 7 इंडेक्सेज़ बोल रहा था, it has to be an inclusive growth, it has to be a growth of its workers, its agricultural sector, its town, its youth, its women, its SC/STs, OBCs and everybody.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Madam, we are discussing the state of economy in India, but, anyone listening to this debate since yesterday will realise that when it comes to facts and figures and insights, Members of the Opposition parties are giving clear arguments to make a strong case. On the other hand, the BJP is having a competition; competition of what, Madam! It is as to how many times they can mention the name of hon. Prime Minister. Well, of course, we do not have any problem regarding that, but, I would like to know why they do not give us facts and figures. The previous three speakers from my party have made common points. What are the points; why is the wealth that is being created not being equally distributed and where? Firstly, equally among all the people of the country and secondly, among the States, irrespective of their political ideologies. Now, let me make a charge which I can substantiate with data. The non-BJP States like Bengal, Tamil Nadu and the Congress-run States are deprived. The unspoken catchline seems to be 'support us politically and we will release funds', 'support us politically and we will not send CBI and ED behind you'. Madam, I will give you one example about MGNREGA. I will raise five points about MGNREGA. Firstly, as we all know, it is an Act of Parliament. It is a right and not a gift depending on the whims and fancies of the Central Government.

Secondly, as per the Act, the payment to a worker who has worked under this scheme is to be made within fifteen days. So, if hundred people have worked on a scheme and if there is any discrepancy arising out of it, if two of them are found guilty, I would like to know why the rest 98 people are deprived. This is most unfortunate and most undesirable. But, this is what is being done. The budget of MGNREGA has been cut by about 30 per cent with respect to last year. But, we are not surprised as

in 2014, on the floor of the Parliament, hon. Prime Minister had called it '*gaddha khodne ka scheme*'; most unfortunately. Fourth point, Madam, is that MGNREGA man days all over the country are falling, but, the Ruling party, the BJP is celebrating it. Today, one of the MPs has called this an indicator of development. This is their way of looking at the economy, but, our approach is different. Fifth point is about job cards. About 7,40,000 job cards have been found to be fake in Uttar Pradesh that means of the total figures, about half is accounted for by Uttar Pradesh. Bengal had about 5,000 fake job cards. I would like to know whether the funds to Uttar Pradesh have been stopped. I am sure the answer is known to all. Now let me read from the BJP manifesto of 2014, I am mentioning it. They had spoken of doubling farmers' income. Did it happen in 2019? No. Again, did it happen in 2023? No. At current growth estimates, the farmers' income will not double before 2030. In Bengal in 2011, a promise was made by the hon. Chief Minister. Most interestingly, it was about doubling farmers' income and I take pride as I come from Bengal in mentioning that as of today it is not doubled, but it has increased three-folds as in the current date. Now, Madam, let me come to public sector undertakings, the PSUs. We have withstood the shock and trauma of demonetization, but how many of us have heard of monetization? This is the instrument of the NITI Aayog to sell out the people's assets, as the name reflects, public sector undertakings. It belongs to the public, it is the asset of the public and the Government is hell-bent upon selling it. Madam, it is like selling the family's jewellery. As you can name it, rail, Air India, BHEL, BSNL, LIC and the list is unending. These were created over decades but now we want to strip the nation of these assets. I proudly belong to the Scheduled Caste community and every time this happens I am hurt and hurt dearly. As every time a PSU is sold, a young SC boy or girl is deprived of his or her right to secure a job. And worst still, there contractual employment engaging is taking the front seat. However, there (in contractual employment) you are not going for reservations. That is a very big concern. And moreover, whenever a PSU is sold, often these people are rendered jobless and it creates unending miseries for the families. Madam, now in understanding the condition of the current economy, we have to understand the condition of States' economies. So, it is very important to discuss cooperative federalism. Our present hon. Prime Minister and hon. Home Minister were both Chief Minister and Home Minister of a State. So, they should understand better what the problems of the States are.* But, as we all know, it is to be done as per constitutional guidelines which are flouted day in and day out. Madam, I appeal to you that next

* Expunged as ordered by the Chair.

week we should have a Short Duration Discussion on the issue of cooperative federalism. Madam, if you notice the House is running so smoothly and it is so good for all of us. Next week also, the opposition should get one Short Duration Discussion or one Calling Attention wherein they can express their concern as opposition and they can at least speak out the pain that the States are in. They can make their points so that the States are benefited. But also there is a flip side to it. The BJP will also benefit from this as though their speeches remain devoid of facts, figures or any reasoning, at least, their speeches will have multiple mentions of the name of the hon. PM. To summarize, I would say that the way the Government is conducting itself, in a nutshell; we can say that their catch-line is that rich should get richer and the poor should get poorer. Now the way the present Government is exploiting the financial interests of the States is most deplorable and is much higher than during the colonial rule. So, I expect that there will be a change of stance. We should think much more about cooperative federalism and act in that direction for the benefit of one and all and the nation as a whole.

Thank you, Madam.

श्रीमती सुलता देव (ओडिशा) : जय जगन्नाथ! ऑनरेबल वाइस-चेयरमैन मैडम, मुझे इतने important topic पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आपकी आभारी हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती फूलो देवी नेतम) : आपके पास सात मिनट का समय है।

श्रीमती सुलता देव : हम 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी तक पहुंच गए हैं। देखा जाए तो हम यहां काफी मुश्किलों से पहुंचे हैं। चाहे रूस और यूक्रेन का conflict हो या कोविड हो, फिर भी हम यहां तक पहुंच गए हैं। मेरे पूर्व के सारे वक्ताओं ने मुद्रास्फीति, जीडीपी ग्रोथ रेट आदि सबके आंकड़े दिए। मैं उन आंकड़ों को नहीं देना चाहूंगी। मैं एक महिला हूं। सारे भारतवर्ष के गांवों और रूरल एरियाज़ से जो महिलाएं belong करती है, मैं उनकी तरफ से बोलना चाहूंगी और दिल से बोलूंगी। मैं एक महिला हूं, तो पहले मैं किचन से बात करूंगी। जीडीपी आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। इसके लिए मैं देश के प्रधान मंत्री का तहेदिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि हमारा देश बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

मगर मैं फिर भी किचन के विषय पर आऊंगी, क्योंकि मैं एक महिला हूं। हम कहीं भी जाएं, मगर किचन में, एक गरीब की थाली में सब चीज़ें न हों, तो कहीं न कहीं, कुछ न कुछ अधूरा ही लगता है, कहीं न कहीं, कुछ न कुछ कमी ही खलती है। आज सबको कहीं न कहीं लग रहा है कि

महंगाई के चलते गरीब की थाली में बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल से आ रही हैं। जिस दिन गरीब की थाली भर जाएगी, उस दिन पूरा देश खुश होगा और जितनी भी ग्रोथ होगी उस दिन जीडीपी की ग्रोथ भी होगी। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यह चाहते हैं कि एक pond हो, जिसमें बड़ी मछली भी रहे और छोटी मछली भी रहे। ऐसा न हो कि बड़ी मछली सारी छोटी मछलियों को निगल जाए। ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कॉरपोरेट सेक्टर भी ग्रो करे और छोटे-से-छोटे, जैसे मैक्रो इकोनॉमी भी बढ़े और माइक्रो इकोनॉमी भी बढ़े, जैसे साधारण लोगों के पास हाथ में पैसा जाएगा, तो यह पैसा देश में रहेगा। FDI investment आता है, यह बहुत अच्छी बात है। बड़े से बड़े कॉरपोरेट हाउस के पास जो पैसा रहेगा, वह पैसा ज्यादातर विदेश में जाएगा। हम लोग अपने देश का पैसा उन लोगों के डेवलपमेंट पर खर्च करें, जो छोटे-से-छोटे काम करते हैं। खासकर मैं एक बात बोलूंगी कि जब unemployment की बात आती है, तो उसमें मैं महिलाओं को भी साथ में लूंगी, क्योंकि हमारी आबादी में 50 से अधिक परसेंट महिलाएं हैं। महिलाओं को कैसे employment मिले और महिला वर्कर कैसे काम करें, इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए। हम आंकड़े देते हैं कि इसमें तो सिर्फ 22 परसेंट महिलाएं हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री, नवीन पटनायक जी का तहेदिल से शुक्रिया अदा करूंगी, जो 7 लाख SHGs बनाकर 70 लाख महिलाओं को काम दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं। अगर महिला के पास कुछ पैसे हों, तो वह बच्चों को अच्छे से रख सकती है, घर को अच्छे से संभाल सकती है। आज SHGs SMEs में परिवर्तित हो चुके हैं। आज चूल्हा-चौका चलाने वाली महिला हमारे यहां लैपटॉप चलाती है, Flipkart एवं Amazon में बिजनेस भी करती है और वह entrepreneur भी बन चुकी है। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने उनको काफी प्रोत्साहन दिया है और इस बात का भी ध्यान रखा है कि कैसे market linking की जाए, किस तरह से उन लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए। हमें मालूम है कि वे सारी महिलाएं मिशन शक्ति की महिलाएं है। वे ही हमारे नवीन ओडिशा की मुख्य ...(**समय की घंटी**)... सर, मेरा टाइम कितना हो गया? अभी चार मिनट हुए हैं, मुझे सात मिनट का समय मिला था। सर, मेरी रिक्वेस्ट है...

MR. CHAIRMAN: Many, many more years to come.

श्रीमती सुलता देव : सर, यह जो नवीन ओडिशा है, नवीन मतलब नया, नये ओडिशा के गठन में ये सभी महिलाएं सारथी बनेंगी। मैं चाहती हूं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा काम में लिया जाए, महिलाओं के लिए ज्यादा स्कोप क्रिएट किये जाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं। अभी 'मनरेगा' के बारे में बात हो रही थी, तो 'मनरेगा' में उनको ज्यादा से ज्यादा काम भी मिलना चाहिए। सर, ओडिशा एक ऐसा स्टेट है, जिसके बारे में आपको भी मालूम है कि वहां पर नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत होती हैं और डिजास्टर्स बहुत होते हैं। हम लोग बार-बार मांग करते हैं कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दीजिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो हमें स्पेशल फोकस स्टेट का स्टेटस दीजिए, जिससे कि सारे राज्यों का एक साथ विकास हो। मान्यवर, नवीन पटनायक जी ने जब ओडिशा के शासन का कार्यभार लिया था, तब 11,108 करोड़ रुपए का बजट था और अभी हमारे स्टेट का बजट 2,30,000 करोड़ रुपए का है। अगर ऐसे ही यह बढ़ता रहेगा, तो देश भी आगे बढ़ता रहेगा। मैं कहना चाहती हूं कि

unemployment को दूर करने के लिए काम हो रहा है, स्किल बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। ओडिशा में जो स्किल सेंटर्स हैं, उनमें छोटे से छोटे बच्चे भी स्किल्ड हो रहे हैं। उनके लिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वे सब जगह पर जा सकें, वे सारी जगहों पर जाकर काम कर सकें।

जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि पूरे देश में रेलवे कनेक्टिविटी हो, नेट कनेक्टिविटी हो, बैंक कनेक्टिविटी हो, लेकिन आज भी हमारे 8 जिलों में रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी हमारे पास 74 परसेंट नेट कनेक्टिविटी है, जबकि देखा जाए, तो 85 परसेंट नेशनल एवरेज है।

MR. CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुलता देव: सर, आज भी हमारे पास 4,549 गांवों में नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बैंक की कनेक्टिविटी भी नहीं है। सरकार डीबीटी की बात करती है, लेकिन जब बैंक्स ही नहीं होंगे, तो डीबीटी कैसे हो सकता है! मैं आपको डीबीटी के बारे में बताना चाहती हूं कि ओडिशा ही पहली स्टेट है, जब 2007-08 के फाइनेंशियल ईयर में 'नरेगा' प्रोजेक्ट के दौरान गंजाम जिले में, मुख्यमंत्री के जिले में, पहले जिलापाल वी.के. पांडियन साहब ने डीबीटी को इंट्रोड्यूस किया था। यही वह ओडिशा है, जो देश को मार्ग दिखाता है। इसके बाद ही डीबीटी आया और डीबीटी के लिए बैंक की जरूरत होती है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री माननीय नवीन पटनायक जी ने 'अमो बैंक योजना' शुरू की है, जिसके कारण हर गांव में बैंक होगा ।

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुलता देव : सर, मैं एक मिनट में कन्क्लूड कर रही हूं। सर, हमारे यहां पर एक 'ममता स्कीम' है। हम लोग चाहते हैं कि..

श्री सभापति : उसका क्या नाम है ? What's the name? ...*(Interruptions)*...

श्रीमती सुलता देव : सर, उस स्कीम का नाम 'ममता' है। सर, मुझे पता है कि यह नाम आपके बहुत करीब है। Thank you, so much, सर, यह 'ममता योजना' है, जो हमारी ओडिशा की सारी महिलाओं के लिए है। अगर इसे देखा जाए, तो इसके कारण ड्रास्टिकली मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, एमएमआर और आईएमआर कम हुई है। मैं अभी भी बोलूंगी कि कहीं फार्मर्स इनकम डबल हुई हो या न हुई हो, पिछले दो साल से हमारे यहां के फार्मर्स की इनकम दोगुनी हो रही है। अगर हम सभी स्टेट्स को साथ में लेकर चलेंगे, तो सारी दुनिया खुश हो जाएगी। मैं अभी यह बोलूंगी, "मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं।" हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा है। यहां सबको मिलजुलकर रहना चाहिए, सबका एक साथ डेवलपमेंट होना चाहिए, तब भारत के लोग भी खुश रहेंगे और सभी देशवासी खुश होंगे। मैं इतना ही कहूंगी। Thank you so much. वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ!

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, some speakers are still left. We will take them tomorrow. I will now continue with the Special Mentions. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, just one point. ...*(Interruptions)*... No; no, it is only this, nothing else. ...*(Interruptions)*... Sir, yesterday you gave ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Just one second. Actually, Derek, you started it so wholesomely that I have got requests from a large number of Members not to curtail their time. We can't have full say. I told them that I have not been very fair to the first speaker. ...*(Interruptions)*... I have not been fair to the first speaker. I gave him only twelve minutes. If I were to increase the time, he would have got more. Okay, what do you want to say?

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the issue is that we had a good debate. Yesterday was for three-and-a-half hours. Today also it was for three-and-a-half hours. Now, you are saying that it will continue tomorrow. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: For half-an-hour. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Okay, for half-an-hour. So, let me make my position clear. Otherwise, tomorrow, you will wonder why I have gone missing. As per the rule, the Minister will reply and, then, that is the end of the discussion. So, lest you do not misunderstand me, tomorrow is a very important day. I seek your indulgence. Our friends in the Congress party are swearing in their Chief Minister in Telangana. We will be happy to be with them. So, I will be missing tomorrow. It is not any boycott. It is a celebration. That's all, Sir.

SHRI A.D. SINGH (Bihar): Sir, I have to express my views on economic matters. But I won't be here before 3 o'clock tomorrow.

MR. CHAIRMAN: We will consider, but you know the outcome.

SHRI A.D. SINGH: Tomorrow, it is for half-an-hour.

MR. CHAIRMAN: Thank you. We will consider.